



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6, 1971/माघ 17, 1892

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6, 1971/MAGHA 17, 1892

इस भाग में भिन्न वृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 2 नवम्बर 1970 तक प्रकाशित किये गये।

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 2nd November 1970.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
370	S. O. 3392, dated 13th October, 1970.	Ministry of Information & Broadcasting	Approval of the films Indian News Review No. 1145, Dasara in Mysore and where Memory Lives/Chaya in their language versions.
370	एस० ओ० 3392 दिनांक 13 अक्टूबर, 1970	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1145, दसरा इन मैसूर, ज़ेयर मेमरी लाइव्स/ छाया औय चयित। मीरेकल आफ पावर फिल्मों को उनके भाषाओं के रूपान्तरों सहित स्वीकृती।
371	S. O. 3393, dated 13th October, 1970.	Ditto.	Approval of the film Indian News Review No. 1145 (Western Edition) in all its language versions.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
371	एस० ओ० 3393 दिनांक 13 अक्तूबर, 1970	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1145 (पश्चिमी संस्करण) फिल्म का उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तर सहित स्वीकृति।
372	S. O. 3394, dated 14th October, 1970	Ministry of Home Affairs.	Suspension of Certain provisions of the Government of Union Territories Act 1963 by the President of India.
372	एस० ओ० 3394 दिनांक 14 अक्तूबर, 1970	गृह मंत्रालय	संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के कतिपय उपबन्धों का भारत का राष्ट्रपति द्वारा निलम्बित करना।
373	S. O. 3395, dated 14th October, 1970	Ministry of Foreign Trade	Jute products shall be subject to quality control and inspection prior to export.
	S. O. 3396, dated 14th October, 1970	Ditto.	The Export of Jute Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1970.
	S. O. 3397, dated 14th October, 1970	Ditto.	Recognition of Export Inspection Agencies for inspection of jute products prior to export.
374	S. O. 3398, dated 15th October, 1970	Ministry of Home Affairs.	15th Day of October, 1970 as the date on which the Laccadive, Minicoy & Amindive Islands (Laws) No. 2 Regulation 1970 shall come into force.
374	का० आ० 3398, दिनांक 15 अक्तूबर, 1970	गृह-मंत्रालय	अक्तूबर 1970 के 15 वें दिन लक्का द्वीप, मिनिक्कोय और अमिन्दीवी द्वीप समूह (विधि) सं० 2 विनियम 1970 का प्रवृत्त तारीख।
375	S. O. 3399, dated 15th October, 1970	Central Board of Direct Taxes.	Further amendment to the Income-tax Rules, 1962.
375	एस० ओ० 3399, दिनांक 15 अक्तूबर, 1970	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	आयकर नियम 1962 में और आगे संशोधन।
376	S. O. 3400, dated 16th October, 1970	Ministry of Petro. & Chem. and Mines & Metals.	Further amendment in the Notification of the Late Ministry of Steel, Mines and Metals (Dept. of Mines & Metals) No. S. O. 2464 dated the 24th July, 1967.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
377	S. O. 3401, dated 19th October, 1970	Election Commission of India.	Calling members of the Legislative Assembly of Kerala to elect a person for the Council of States before the 9th Nov. 1970.
377	एस० ओ० 3401, दिनांक 19 अक्तूबर, 1970	भारत निर्वाचन आयोग	9 नवम्बर, 1970 से पूर्व केरल राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में एक व्यक्ति का निर्वाचन।
	S. O. 3402, dated 19th October, 1970	Ditto.	Appointment of dates in pursuance of Notification No. 100/CS-KL/2/70 dated 19th October, 1970.
	एस० ओ० 3402, दिनांक 19 अक्तूबर, 1970	तद्वैव	अधिसूचना सं० 100/रा० सं० केरल/2/70 तारीख 19 अक्तूबर, 1970 के अनुसरण में निर्वाचन होने वाले सम्बन्धि तारीखें।
	S. O. 3403, dated 19th October, 1970	Ditto.	Fixation of hours for the election to the Council of States.
	एस० ओ० 3403, दिनांक 19 अक्तूबर, 1970	तद्वैव	राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन समय।
	S. O. 3404, dated 19th October, 1970	Ditto.	Secretary Kerala Legislative Assembly, Trivandrum is the Returning Officer of the election to the Council of States.
	एस० ओ० 3404, दिनांक 19 अक्तूबर, 1970	तद्वैव	सचिव, केरल विधान सभा, त्रिवेन्द्रम को रिटर्निंग आफिसर के रूप में राज्य सभा के निर्वाचन के लिए नियुक्ति।
	S. O. 3405, dated 19th October, 1970	Ditto.	Joint Secretary, Kerala Legislative Assembly, Trivendrum to assist the Returning Officer.
	एस० ओ० 3405, दिनांक 19 अक्तूबर, 1970	तद्वैव	संयुक्त सचिव, केरल विधान सभा त्रिवेन्द्रम, को रिटर्निंग आफिसर के सहायक नियुक्त।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
378	S. O. 3483, dated 20th October, 1970	Ministry of Industrial Dev. & Internal Trade.	Further amendment in the Order of the late Ministry of Industrial Dev. & Company Affairs No. S. O. 4460/18A/IDRA/67 dated the 14th Dec. 1967.
	का० आ० 3483, दिनांक 20 अक्टूबर, 1970	औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय	अधिसूचना आदेश सं० का० आ० 4460/18 क/आई० डी० आर० ए०/67 तारीख 14 दिसम्बर, 1967 में और आगे संशोधन।
379	S. O. 3484, dated 20th October, 1970	Ditto.	Taking over the management of Chhaganal Textiles Mills Pvt. Ltd., Chalisgaon.
	का० आ० 3484, दिनांक 20 अक्टूबर, 1970	तदैव	छगनलाल टैक्सटाइल मिल्स प्रा० लि० चालिसगांव का प्रबन्ध अधिकार में लेना।
380	S. O. 3485, dated 20th October, 1970	Ministry of Foreign Trade.	Further order to amend the Imports (Control Order, 1955
	का० आ० 3485, दिनांक 20 अक्टूबर, 1970	विदेश व्यापार मंत्रालय	आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 में और आगे संशोधन करने का आदेश।
381	S. O. 3486, dated 21st October, 1970	Ministry of Foreign Trade.	Frozen lobster tails shall be subject to quality Control and inspection prior to export.
	का० आ० 3486, दिनांक 21 अक्टूबर, 1970	विदेशी व्यापार मंत्रालय	झिगी मछली के प्रशतित पृष्ठ. भाग निर्यात से पूर्व गुण नियं- त्रण और निरीक्षण के अध्यधीन।
382	S. O. 3487, dated 22nd October, 1970	Ditto.	Transmission line towers shall be subject to quality Control and inspection prior to export.
	का० आ० 3487, दिनांक 22 अक्टूबर, 1970	तदैव	संचरण लाइन टावर निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अध्यधीन।
383	S. O. 3488/IDRA/18G/69, dated 22nd October, 1970.	Ministry of Industrial Dev. & Internal Trade.	Further amendment to the Cement Control Order 1967.
	एस० ओ० 3488/ आई० डी० आर० ए०/ 18 छ/69 दिनांक 22 अक्टूबर, 1970	औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार	सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 में और आगे संशोधन।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
384.	S. O. 3489, dated 22nd October, 1970	Ministry of Finance.	Notifying:—(i) any Corporation established by a Central, State or Provincial Act; (ii) any Company in which all the shares are held by the Govt. or the Reserve Bank of India or a Corporation owned by that Bank; and (iii) any undertaking or body including a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), financed wholly by the Govt. for sub-clause (f) of cl. (iii) of sub-sec. (3) of sec. 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).
	एस० ओ० 3489 दिनांक 22 अक्टूबर 1970	वित्त मंत्रालय	अनुमूचित करती है:— (i) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम; (ii) किसी कम्पनी जिसमें सभी शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या उस बैंक के स्वामित्व वाले निगम द्वारा धृत है; और (iii) सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित कोई उपक्रम या निकाय जिसमें सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी सम्मिलित है के लिए आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 194 क की उपधारा (3) के खण्ड (iii) के उप-खण्ड च के अनुसरण।
385.	S. O. 3490, dated 23rd October, 1970.	Ministry of Food, Agri., Com. Dev. & Co-operation.	Fixation of maximum prices at which Vegetable oil products may be sold in various Zones w.e.f. the 24th October, 1970.
	का० आ० 3490 दिनांक 23 अक्टूबर 1970	खाद्य कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	अधिकतम कीमते जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों का विभिन्न जोनों में 24 अक्टूबर, 1970 से विक्रय करने का नियतीकरण

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
386.	S. O. 3491, dated 24th October, 1970 एस० ओ० 3491 दिनांक 24 अक्टूबर 1970	Ministry of Information & Broadcasting. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Approval of the films in their language versions. भारतीय भाषाओं के रूपान्तरो सहित फिल्मों की स्वीकृति।
	S. O. 3492, dated 24th October, 1970 एस० ओ० 3492 दिनांक 24 अक्टूबर 1970	Ditto.	Approval of the film in its language version. भारतीय भाषा के रूपान्तर सहित फिल्म की स्वीकृति।
	S. O. 3493, dated 24th October 1970 एस०ओ० 3493, दिनांक 24 अक्टूबर 1970	Ditto.	Approval of the film in its various language version. भारतीय भाषा के रूपान्तर सहित फिल्म की स्वीकृति।
	S. O. 3494, dated 24th October, 1970 एस०ओ० 3494, दिनांक 24 अक्टूबर 1970	Ditto.	Approval of the film in its various language version. भारतीय भाषा के रूपान्तर सहित फिल्म की स्वीकृति।
387.	S. O. 3495, dated 24th October, 1970 एस०ओ० 3495, दिनांक 24 अक्टूबर 1970	Ministry of Foreign Trade. विदेशी व्यापार मंत्रालय	Continuation to have effect of the Order of the Govt. of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 3981, dt. 22-12-1965 for a further period upto the 21st December 1971. भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 3981, दिनांक 22 दिसम्बर 1965 का प्रभाव 21 दिसम्बर 1971 तक की अवधि के लिए और बना रहेगा।
388.	S. O. 3546, dated 26th October, 1970 एस०ओ० 3546, दिनांक 26 अक्टूबर 1970	Ministry of Food, Agri., Com., Dev., & Co-operation. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय	Constitution of the Central Seed Committee. केन्द्रीय बीज समिति का संगठन।
389.	S. O. 3547, dated 27th October, 1970	Cabinet Secretariat.	Further amendment to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961.
390.	S. O. 3548, dated 27th October, 1970	Ditto.	The Government of India (Allocation of Business) (eighty-seventh Amendment) Rules, 1970.

Issue No.	No. and date	Issued by	Subject
391.	S. O. 3549, dated 28th October, 1970	Ministry of Foreign Trade.	Dr. K. Mathew Kurian elected a member of the Coir Board vice Shri Sher Khan.
392.	S. O. 3550, dated 28th October, 1970	Ditto.	Appointment of Shri A. Datta Majumdar, Dy. Press Registrar Office of the Registrar of Newspapers for India, Min. of I & B. to exercise the powers of the Controller.
	का०ग्रा० 3550, दिनांक 28 अक्टूबर 1970	तथैव]	भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उप-प्रेस रजिस्ट्रार श्री ए० दत्त मजूमदार को नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्ति।
393.	S. O. 3551, dated 30th October, 1970	Ditto.]	Appontment of Shri K. S. Thakur, Registration Supervisor, office of the Registrar of Newspapers for India, Min. of I. & B. New Delhi to exercise the powers of the Controller.
	एस०ओ० 3551, दिनांक 30 अक्टूबर 1970	तथैव	भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीयन पर्यवेक्षक श्री के० एस० ठाकुर को नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्ति।
394.	S. O. 3552, dated 31st October, 1970.	Ministry of Information & Broadcasting	Approval of the films in all their language Versions.
	एस०ओ० 3552, दिनांक 31 अक्टूबर 1970	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित फिल्मों की स्वीकृति
	S. O. 3553, dated 31st October, 1970	Ditto.	Approval of a film in all its language Version.
	एस०ओ० 3553, दिनांक 31 अक्टूबर 1970	तथैव	भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित एक फिल्म की स्वीकृति।

Issue No.	No. and date	Issued by	Subject
395.	S. O. 3639, dated 2nd November, 1970	Ministry of Labour, Emp., & Rehabilitation.	Constituting a National Industrial Tribunal with Shri Mahesh Chandra as the Presiding Officer
	का०आ० 3639, दिनांक 2 नवम्बर 1970	श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय	राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन और श्री महेश चन्द्र को उसके पीठासीन अधिकारी नियुक्त ।
	S. O. 3640, dated 2nd November 1970.	Ditto.	Adjudication of an industrial dispute between the employers in relation to the Air India and the Indian Airlines and their work-men by a National Tribunal.
	का०आ० 3640, दिनांक 2 नवम्बर 1970	तथैव	एयर इंडिया और दि इंडियन एयर लाइन्स से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विवाद का न्याय-निर्णयन एक राष्ट्रीय अधि-करण द्वारा ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए ।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर)

केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं ।

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st February 1971

S.O. 623/IDRA/5/71.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rule 8 of the Central Advisory Council (Precedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri V. V. Chari to be member of the Central Advisory

Council of Industries till the 4th March, 1972, in place of Prof. R. K. Hazari and directs that the following further amendment shall be made in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 971 dated the 5th March, 1970 as amended vide No. S.O. 1367 dated the 9th April, 1970, namely:—

In the said Order, for entry No. 17 relating to Prof. R. K. Hazari, the following entry shall be substituted, namely:

“17. Shri V. V. Chari, Deputy Governor, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay-1.”

[No. 1(3)Lic.Pol./69.]

R. C. SETHI, Under Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1971

एत० प्रो० 623-आई० डी० आर० ए० /5/71—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम् केन्द्रीय सलाहकार परिषद (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी० वी० चारी को प्रो० आर० के० हजारी के स्थान पर 4 मार्च, 1972 तक के लिए उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त करती है तथा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० एस० प्रो० 971 दिनांक 5 मार्च, 1970 जिसे सं० एस० प्रो० 1367 दिनांक 9 अप्रैल, 1970 के द्वारा संशोधित किया गया, में निम्नलिखित और आगे संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त आदेश में प्रो० आर० के० हजारी से संबंधित प्रविष्टि संख्या 17 के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

“17 श्री बी० वी० चारी,
डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया,
केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई-1” ।

[संख्या 1(3) एल० पी०/69]

आर० सी० सेठी, अवर सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 28th December 1970

S.O. 624.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, with the consent of the Government of Meghalaya, hereby entrusts to that Government, the functions of the Central Government under the Census Act 1948 (37 of 1948), except those under section 3, sub-section (1) of section 4 and sub-sections (1) and (2) of section 18 of the said Act, in relation to its territories

(except the area comprised within the municipality of Shillong), subject to the following conditions, namely:—

- (a) that in the exercise of such functions the said Government shall comply with such general or special directions as the Central Government may, from time to time, issue; and
- (b) that notwithstanding this entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[No. 1/10/70-Ad.II.]

गृह मंत्रालय

(भारत के महापंजीकार का दफ्तर)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 624.—संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मेघालय सरकार की सहमति से ए० द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यों उक्त अधिनियम की धारा 3, धारा 4 की उपधारा (1) एवं धारा 18 के उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत कार्य को छोड़कर मेघालय के क्षेत्र के सम्बन्ध में (शिलांग की नगर पालिका के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, को छोड़कर निम्नलिखित शर्तों पर मेघालय सरकार को सौंपे हैं :—

- (i) कि इन कार्यों के निष्पादन में उक्त सरकार उन सभी साधारण व विशेषनिर्देशों का पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर जारी करे, और
- (ii) ये कार्य इस प्रकार सौंपने के बावजूद केन्द्रीय सरकार उपरोक्त कार्यों को यदि उचित समझे तो वह स्वयं कर सकती है।

[सं० 1/10/70-ए०डी० 11]

S.O. 625.—In exercise of the powers conferred by Section 70 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government, after consulting the Government of Assam, hereby declares that any reference to "State" in the Census Act 1948 (37 of 1948), shall in its application to Meghalaya, be construed as a reference to the territories of Meghalaya (except the area comprised within the Municipality of Shillong) and any reference to "State Government" in the said Act shall in its application to Meghalaya be construed as a reference to the Central Government.

[No. 1/10/70-Ad.II.]

A. CHANDRA SEKHAR,
Registrar General, India and ex-officio
Jt. Secy.

एस०ओ० 625.—असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 70 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, असम सरकार से परामर्श करने के बाद एतद्वारा यह घोषित करती है कि जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) में "राज्य" का कोई भी उल्लेख, जहां तक उसका मेघालय के लिए प्रयुक्त होने का सम्बन्ध है, मेघालय के क्षेत्र (शिलांग के नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर) के लिए उल्लेख माना जाय और उक्त अधिनियम में मेघालय के लिए प्रयुक्त होने के संदर्भ में "राज्य सरकार" का कोई भी उल्लेख केन्द्रीय सरकार के लिए माना जाय।

[सं० 1/10/70-ए० डी० II]

ए० चन्द्रशेखर,
भारत सरकार के महापंजीकार और पदेन संयुक्त
सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th January 1971

S.O. 626.—In the Ministry of Finance Notification No. 8128-EV/70, dated the 6th November, 1970, the following corrections may be made:—
Para 1(1)

Word "Sixth" appearing in 2nd line should read as "Fifth".

[No. 37(4)-EV/70.]

MEHAR SINGH, Under Secy.

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th January 1971

S.O. 627.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O.3020 dated the 28th July, 1970, published on page 4073 of the Gazette of India, Part II-Section 3 sub-section (ii) dated, the 19th September, 1970 the following corrections may be made:—

(i) Under the heading "Designs" relating to the description of obverse of "Ten Rupees" for the words "दस" in Hindi read "दस"

(ii) Under the heading "Designs" relating to the description of reverse of "Ten Rupees" for the word "flating" read "floating".

[No. F.1/1/67-Coin/Pt.I.]

M. K. VENKATARAMAN, Under Secy.

(Department of Banking)

New Delhi, the 15th January 1971

S. O. 628.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 15th January, 1971

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	18,65,12,000
		Rupee Coin	3,45,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,20,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
		(a) Internal	35,16,000
		(b) External
		(c) Government Treasury Bills	17,47,12,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balances Held Abroad*	110,25,61,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	Investments**	106,04,19,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government
		(ii) State Governments @	185,29,07,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	374,50 35,000
(a) Government :—		(ii) State Co-operative Banks††	294,49,15,000
(i) Central Government	349,82,60,000	(iii) Others	2,04,75,000

Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund—

(ii) State Governments		4,90,02,000	(a) Loans and Advances to:—	
			(i) State Governments	34,20,49,000
			(ii) State Co-operative Banks	22,12,97,000
			(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(b) Banks—			(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,59,42,000
(i) Scheduled Commercial Banks	190,62,04,000		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund—	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	9,22,65,000		Loans and Advances to State Co-operative Banks	5,27,67,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	88,92,000		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund—	
(iv) Other Banks	29,40,000		(a) Loans and Advances to the Development Bank	27,93,71,000
(c) Others	89,09,80,000		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
Bills Payable	44,94,60,000		Other Assets	37,90,84,000
Other Liabilities	97,43,24,000			
Rupees	1246,23,27,000		Rupees	1246,23,27,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary over-drafts to State Governments.

†Includes Rs. 170,82,50,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 13th day of January, 1971.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 8th day of January, 1971.
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	18,65,12,000		Gold Coin and Bullion :—		
			(a) Held in India	182,53,11,000	
Notes in circulation	4112,40,46,000		(b) Held outside India	..	
Total Notes issued		4131,05,58,000	Foreign Securities	271,42,00,000	
			TOTAL		453,95,11,000
			Rupee Coin		55,19,00,000
			Government of India Rupee Securities		3621,91,47,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
TOTAL LIABILITIES		4131,05,58,000	TOTAL ASSETS		4131,05,58,000

Dated the 13th day of January, 1971.

(Sd.) S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F. 3 (3)-BC/71.]

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1971

एस० ओ० 628.—8 जनवरी, 1970 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकलाप का विवरण ।

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	18,65,12,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,45,000
		छोटा सिक्का	4,20,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल:—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरिकरण) निधि	37,00,00,000	(क) देशी	35,16,000
		(ख) विदेशी
		(ग) सरकारी खजाना बिल	17,47,12,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	110,25,61,000
जमा-राशियां :—		निवेश**	106,04,19,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	349,82,60,000	(i) केन्द्रीय सरकार को
(ii) राज्य सरकारें	4,90,02,000	(ii) राज्य सरकारों को@	185,29,07,000
		ऋण और अग्रिम :—	
(ख) बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	374,50,35,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	190,62,04,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	294,49,15,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	9,22,65,000	(iii) दूसरों को	2,04,75,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	

देयताएं	रुपये	ग्रास्तियां	रुपये
		(क) ऋण और अग्रिम :-	
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	88,92,000	(i) राज्य सरकारों को	34,20,49,000
(iv) अन्य बैंक	29,40,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	22,12,97,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को
(ग) अन्य	89,09,80,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	9,59,42,000
देय बिल	44,94,60,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	5,27,67,000
अन्य देयताएं	97,43,24,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	27,93,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश अन्य ग्रास्तियां 37,90,84,000
रुपये	1246,23,27,000	रुपये	1246,23,27,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 170,82,50,000 रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 13 जनवरी, 1970।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी, 1971 की 8 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा

इस विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	भास्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए			सोने का सिक्का और बुलियन:—		
नोट .	18,65,12,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचलन में नोट	4112,40,46,000		(ख) भारत के बाहर रखा		
			हुआ	
			विदेशी प्रतिभूतियां	271,42,00,000	
जारी किए गए कुल नोट		4131,05,58,000			
			चोड़		453,95,11,000
			रुपये का सिक्का		55,19,00,000
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिभूतियां		3621,91,47,000
			देशी विनिमय बिल और		
			दूसरे वाणिज्य-पत्र
कुल देयताएं		4131,05,58,000	कुल भास्तियां		4131,05,58,000

तारीख 13 जनवरी, 1971

(ह०) एस० जगन्नाथन,
गवर्नर ।

[सं० एक० 3 (3)—वी० सी०/71]

New Delhi, the 27th January 1971

S.O. 629.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 15th January, 1971

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	4,56,32,000
		Rupee Coin	3,22,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,79,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund . .	172,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
		(a) Internal	35,16,000
		(b) External
		(c) Government Treasury Bills	9,71,67,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	Balances Held Abroad*	103,29,01,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	Investments**	103,54,72,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government
		(ii) State Governments@	226,55,00,000
Deposits—		Loans and Advances to :—	
(a) Government—		(i) Scheduled Commercial Banks†	377,67,05,000
		(ii) State Co-operative Banks ‡	294,35,13,000
		(iii) Others	1,87,75,000
(i) Central Government	355,79,96,000		

(d) State Governments	4,92,54,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(b) Banks		(a) Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	187,06,28,000	(i) State Governments	34,19,52,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	8,90,36,000	(ii) State Co-operative Banks	21,94,84,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,49,3,000	(iii) Central Land Mortgage Banks
(iv) Other Banks	26,35,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,59,42,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	
		5,14,95,000	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
(e) Others	87,73,57,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	27,93,71,000
Bills Payable	46,39,77,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank
Other Liabilities	107,93,21,000	Other Assets	37,96,21,000
	Rupees 1258,77,47,000		Rupees 1258,77,47,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 199,16,50,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 20th day of January, 1971.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 15th day of January, 1971.
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	4,56,32,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	<u>4145,98,75,000</u>		(a) Held in India	182,53,11,000	
Total Notes issued		4150,55,07,000	(b) Held outside India	
			Foreign Securities	<u>261,42,00,000</u>	
			TOTAL		443,95,11,000
			Rupee Coin		54,90,37,000
			Government of India Rupee Securities		<u>3651,69,59,000</u>
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper
TOTAL LIABILITIES		<u>4150,55,07,000</u>	TOTAL ASSETS		<u>4150,55,07,000</u>

Dated the 20th day of January, 1971.

(Sd.) S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F. 3(3)-BC/71]
K. YESURATNAM, Under Secy.

CORRIGENDUM

In the Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on 27th November 1970 published at pages 5605-6 of part II section 3(ii) of the Gazette of India issue dated 19th December 1970 the figure against the head "Other Assets" on the assets side of the statement should be read as 33,96,92,000 instead 38,96,92,000

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1971
 ए०० 629. - 15 जनवरी 1971 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकलाप का विवरण।
 बैंकिंग विभाग

देयताएं	रुपये	भास्तियां	रुपये
चकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	4,56,32,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,22,000
		छोटा सिक्का	3,79,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(क) देशी	35,16,000
		(ख) विदेशी
		(ग) सरकारी खजाना बिल	9,71,67,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	103,29,01,000
जमा-राशियां :—		निवेश**	103,54,72,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	355,79,96,000	(i) केन्द्रीय सरकार को
(ii) राज्य सरकारें	4,92,54,000	(ii) राज्य सरकारों को @	226,55,00,000
		ऋण और अग्रिम :—	
(ख) बैंक		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	377,67,05,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	187,06,28,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	294,35,13,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,90,36,000	(iii) दूसरों को	1,87,75,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
		(ब) ऋण और अग्रिम:—	
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	74,93,000	(i) राज्य सरकारों को	34,19,52,000
(iv) अन्य बैंक	26,85,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	21,94,84,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को
(ग) अन्य	87,73,57,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	9,59,42,000
देय बिल	46,39,77,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	5,14,95,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश:—	
अन्य देयताएं	107,93,21,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	27,93,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश अन्य आस्तियां	37,96,21,000
रुपये	1258,77,47,000	रुपये	1258,77,47,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ब) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 189,16,50,000 रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख: 20 जनवरी, 1971।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जनवरी 1971 की 15 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा
इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए			सोने का सिक्का और बुलियन :-		
नोट	4,56,32,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचलन में नोट	4145,98,75,000		(ख) भारत के बाहर रखा		
			हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	261,42,00,000	
जारी किए गए कुल नोट		4150,55,07,000			
			बोड़		443,95,11,000
			रुपये का सिक्का		54,90,37,000
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिभूतियां		3651,69,59,000
			देशी विनिमय बिल और		
			दूसरे वाणिज्य पत्र		..
कुल देयताएं		4150,55,07,000	कुल आस्तियां		4150,55,07,000

तारीख : 20 जनवरी, 1971।

(ह०) एस० जगन्नाथन,
गवर्नर।

[सं० फ० 3(3)-बी० सी०/71]

के० येसुरल्लम, अनु-सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 28th October 1970

S.O. 630.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the under-mentioned temple to be a place of public worship of renown throughout the state of Tamil Nadu for the purpose of the said section.

Shri Balasarduleeswarar Temple, Nellorepet, Gudiyattam North Arcot District.

[No. 175 (F. No. 176/48/70-IT) (AI).]

B. MADHAVAN, Under Secy.

राजस्व और बीमा विभाग

आयकर

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1970

एस० ओ० 630.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नवर्णित मन्दिर को, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण तमिल नाडु राज्य में सार्वजनिकपूजा के स्थान के रूप में अधिसूचित करती है,

श्री बालासुरदुली स्वराय मन्दिर नेल्लोरेपेट गुडियत्तम, उत्तरी आर्कोट जिला।

[सं० 175 (फा० सं० 176/46/70—आई० टी० (ए० आई०))]

बी० माधवन्, अवर सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 22nd January 1971

S.O. 631.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Council of Scientific & Industrial Research, the "Prescribed Authority" for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961):

INSTITUTION

The Oil Technologists Association of India, Kanpur.

[No. 10 (F. No. 203/17/70-IT (AII)).]

S. N. NAUTIAL, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

आयकर

नई दिल्ली, 22 जनवरी 1971

एस० ओ० 631.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा,

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए”
“विहित” प्राधिकरण अनुमोदित किया गया है।

संस्था

दि आयल टेक्नालोजिस्ट्स एसोसिएशन आफ इण्डिया, कानपुर

[सं० 10 फा० सं० 203/17/70-आई० टी० (ए० 11)]

एस० एन० नोटियाल, उप सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th January 1971

S.O. 632.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and Sub-rule (3) of rule 9 read with sub-rule (2) of rule 9 and sub-rule (3) of rule 8 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as members of the Advisory Panel of the said Board at Madras with effect from 1st January, 1971 to 30th June, 1971:—

1. Shri T. Neelakanthan
2. Smt. Soundra Kailasam
3. Shri Pakala Suryanarayana Rao
4. Shri Mohd. Yousuf Kokan
5. Shri M. Govindan
6. Smt. C. L. Meenakshi Amma
7. Shri P. V. Chalapatheeswara Rao
8. Prof. M. Mariappa Bhat
9. Smt. Marry Clubwala Jadav.

[No. F. 11/2/71-FC.]

VIRENDRA D. VYAS, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली 8 जनवरी, 1971

एस० ओ० 632.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (संसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उपनियम (2) तथा नियम 8 के उपनियम (3) के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से पारमर्श करके निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1971 से 30 जून, 1971 तक उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल का फिर से सदस्य नियुक्त किया है:—

- 1 श्री टी० नीलकण्ठन
- 2 श्रीमती सुन्दरा कैलासम्
- 3 श्री पकासा सूर्यनारायण राव
- 4 श्री मुहम्मद यूसुफ कोकन
- 5 श्री एम० गोविन्दन
- 6 श्रीमती सी० एल० मीनाक्षी अम्मा
- 7 श्री पी० बी० चलपतीश्वर राव
- 8 प्रो० एम० मरिअप्पा बट्ट
- 9 श्रीमती मेरी क्लबवाला जादव

[संख्या एक० 11/2/71-एफ० सी०]

वीरेन्द्र देव व्यास, उप सचिव

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 28th November 1970

8.O. 633.—M/s Coles Cranes of India Ltd., 517 Barrackpore Trunk Road, Kamarhatty Calcutta-58 were granted a C.C.P. No. P/J/2332420 dt. 6th May, 1970 for import of second hand Dry Photo Copier Model 107, for Rs. 1,890/- from General Area. They have applied for issue of a duplicate C.C.P. on the ground that the original has been misplaced/lost/without having been registered with any Customs authority and utilised at all.

2. In support of this contention M/s. Coles Cranes of India Ltd., 517 Barrackpore Trunk Road, Kamarhatty, Calcutta-58 have produced an affidavit. The undersigned is satisfied that the original licence has been lost/misplaced. Therefore, in exercise of the powers conferred under Clause 9(c) of the Import Control Order 1955 dated 7th December, 1955 as amended, the original customs purpose copy is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of Customs clearance permit is being issued separately.

[No. Cranes.4(1)/69-70/RM.6.]

G. S. SHARMA,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार संस्थान

मुख्य निर्यात आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली दिन क 28 नवम्बर 1970

एस० ओ० 633.—सी० श्री कोल्ज क्रैन्स आफ इण्डिया लि० 517 बैरकपुर ट्रंक रोड, कमर हट्टी कलकत्ता-58 को सामान्य क्षेत्र से इस्तेमाली ड्राई फोटो कॉपीयर मॉडल 107 का आयात करने के लिए 1,890 रुपये का सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी० जे० 2332420 दिनांक 6-5-70 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने अनुलिपि सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट बिना किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए और उपयोग किए खो गया है। अस्थानस्थ हो गया है।

2. इस तर्क के समर्थन में सर्वश्री कोल्ज क्रैन्स आफ इण्डिया लि० 517 बैरकपुर ट्रंक रोड, कमर हट्टी न एक शपथ पत्र जमा किया है। प्रधोह स्ताक्षरी इससे सतुष्ट है कि मूल लाइसेंस खो गया है। अस्थानस्थ हो गया है। इसलिए यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर एतद् द्वारा मूल सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति रद्द की जाती है।

3. सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है

[सं० क्रैन्स 4 (1)/69-70/आर० एम०-6]

(जी० एस० शर्मा,)

उप-मुख्य निर्यात, आयात निर्यात

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 14th January 1971

S.O. 634.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby appoints Dr. N. V. A. Narasimham, Director of Transport Research, Ministry of Shipping and Transport, as a member of the Inter-State Transport Commission, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 1618, dated the 11th April, 1969, namely:—

In the said notification, for item (3), the following item shall be substituted, namely:—

“3. Dr. N. V. A. Narasimham, Director of Transport Research, Ministry of Shipping and Transport, New Delhi.”

[No. 23-T(11)/67.]

K. C. JOSHI, Dy. Secy.

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1971

का०आ 634.—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डा० एन० वी० ए० नरसिंहम, परिवहन अनुसंधान-निदेशक, पोतपरिवहन और परिवहन मंत्रालय को अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1618, ता० 11 अप्रैल, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मव (3) के स्थान पर निम्नलिखित मव प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“3 डा० एन० वी० ए० नरसिंहम, परिवहन अनुसंधान, पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली।”

[सं० 23-टी० (II)/67]

के० सी० जोशी, उपसचिव ।

MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

New Delhi, the 12th January 1971

S.O. 635.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 68, dated the 21st February, 1958, the President hereby directs that, in respect of the posts in the General Central Service, Class III and the General Central Service, Class IV, specified in column I of parts I and II of the Schedule hereto, the authority specified in column 2 of the said Schedule shall be the Appointing Authority and the authorities specified in columns 3 and 5 of the said Schedule shall be the Disciplinary Authority and the Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column 4 thereof.

THE SCHEDULE

PART I—General Central Service, Class III

Description of Post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties (Disciplinary Authority) and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
Office of the Chief Pay and Accounts Officer, New Delhi.				
(i) Subordinate Accounts Service	Chief Pay and Accounts Officer	Chief Pay and Accounts Officer	All	Secretary
(ii) Other Class III posts	Deputy Chief Pay & Accounts Officer.	Deputy Chief Pay & Accounts Officer.	All	Chief Pay & Accounts Officer.
Office of the Pay and Accounts Officer, Bombay/Calcutta/Madras.				
(i) Subordinate Accounts Service	Chief Pay and Accounts Officer.	Chief Pay and Accounts Officer.	All	Secretary
(ii) Other Class III posts	Pay and Accounts Officer.	Pay and Accounts Officer.	All	Chief Pay and Accounts Officer.
Directorate of Sugar and Vanaspathi, New Delhi.				
All posts	Administrative Officer.	Administrative Officer.		Chief Director.
National Sugar Institute, Kanpur				
All Posts	Senior Administrative Officer.	Senior Administrative Officer.	All	Director.
Offices of the Regional Director (Food), New Delhi/Bombay/Calcutta/Madras (including Residuary Units).				
All posts	Deputy Director General (Food)/Regional Director (Food).	Deputy Director General (Food)/Regional Director (Food).	All	Director General of Food/Joint Secretary.
Offices of the Deputy Technical Adviser and Units thereunder.				
All posts	Executive Director.	Executive Director. Deputy Technical (i) to (iv) Adviser.	All	Joint Secretary. Executive Director.

Grain Storage Research and Training Centre, Hapur. All posts	Director.	Director.	All	Director General of Food/Joint Secretary.
Indian Grain Storage Institute, Hapur, (including out-station units). All posts	Project Co-ordinator	Project Co-ordinator	All	Director General of Food/Joint Secretary.
Office of the Officer-in-Charge, Defence Grinding/ Tea Agreement. All posts	Chief Director of Purchase.	Chief Director of Purchase.	All	Director General of Food/Joint Secretary.

THE SCHEDULE
Part II—General Central Service, Class IV

Description of Post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties (Disciplinary Authority and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11))		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
Offices of the Chief Pay and Accounts Officer, New Delhi. All posts.	Deputy Chief Pay and Accounts Officer.	Deputy Chief Pay and Accounts Officer.	All	Chief Pay and Accounts Officer.
Office of the Pay and Accounts Officer, Bombay/Calcutta/Madras. All posts	Pay and Accounts Officer.	Pay and Accounts Officer.	All	Chief Pay and Accounts Officer.
Directorate of Sugar and Vanaspati, New Delhi. All posts	Administrative Officer.	Administrative Officer.	All	Chief Director.
National Sugar Institute, Kanpur. All posts	Senior Administrative Officer.	Senior Administrative Officer.	All	Director.
Offices of the Regional Director (Food), New Delhi/Bombay/Calcutta/Madras (including Residuary units). All posts	Assistant Director.	Assistant Director.	All	Deputy General Regional Director (Food).
Grain Storage Research and Training Centre, Hapur. All posts	Assistant Director.	Assistant Director.	All	Director.
Indian Grain Storage Institute, Hapur (including out-station units). All posts	Administrative Officer	Administrative Officer.	All	Project Coordinator.
Offices of Deputy Technical Adviser & Units there-under. All posts	Deputy Technical Adviser	Deputy Technical Adviser.	All	Executive Director.

Office of the Officer-in-Charge, Defence Grinding/
Tea Agreement.

All posts

Chief Director of Purchase

Chief Director of Purchase

All

Director General
of Food/Joint
Secretary.

[No. C11012/1/70 AVU.]

R. S. GUPTA, Dy. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1971

का०आ० 635—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 68 तारीख 21 फरवरी, 1958 को अधिकांत करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग-3 और साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग-4 के पदों के संबंध में इसकी अनुसूची के भाग I और II के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उसके स्तम्भ 4 में व निर्दिष्ट शास्तियों की बाबत क्रमशः आनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

भाग 1—साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग -3

पद विवरण	नियुक्ति-प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (आनुशासनिक प्राधिकारी) और शास्तियां जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 के मद संख्याओं के अपील- प्राधिकारी संदर्भ में)		
		प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5
मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी का कार्यालय, नई दिल्ली				
(I) अधीनस्थ लेखा सेवा	मुख्य वेतन तथा अधिकारी	लेखा- अधिकारी	लेखा- सभी अधिकारी	सचिव
(II) वर्ग-3 के अन्य पद	उपमुख्य वेतन तथा अधिकारी	उपमुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी	सभी लेखा-अधिकारी	मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी

1	2	3	4	5
(I) अधीनस्थ लेखा सेवा	मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी	मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी	सभी	सचिव ।
(II) वर्ग -3 के अन्य पद	वेतन तथा लेखा अधिकारी	वेतन तथा लेखा-अधिकारी	सभी	मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी
शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय, नई दिल्ली ।				
सभी पद	प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	सभी	मुख्य निदेशक
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ।				
सभी पद	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधि-कारी	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधि-कारी	सभी	निदेशक
क्षेत्रीय निदेशक (खाद्य) के कार्यालय, नई दिल्ली/मुंबई/कलकत्ता/मद्रास (जिसमें अवशिष्टीय एकक भी सम्मिलित है)				
सभी पद	उपमहानिदेशक (खाद्य) क्षेत्रीय निदेशक (खाद्य)	उपमहानिदेशक (खाद्य) क्षेत्रीय निदेशक (खाद्य)	सभी	महानिदेशक, खाद्य/संयुक्त सचिव
उप-तकनीकी सलाहकार का कार्यालय और उसके अधीन एकक ।				
सभी पद	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक उप-तकनीकी सलाहकार	सभी (i) से (iv)	संयुक्त सचिव कार्यपालक निदेशक
अनाज भण्डारकरण अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, हापुड़ ।				
सभी पद	निदेशक	निदेशक	सभी	महानिदेशक, खाद्य/संयुक्त सचिव
भारतीय अनाज भण्डारकरण संस्थान, हापुड़ (जिसमें बाहर के एकक भी सम्मिलित हैं)				
सभी पद	परियोजना समन्वयकर्ता	परियोजना समन्वयकर्ता	सभी	महानिदेशक, खाद्य/संयुक्त सचिव ।

1	2	3	4	5
रक्षा विभाग के लिए पिसाई/ बाय करार के भारसाधक अधिकारी का कार्यालय ।				
सभी पद	मुख्य निदेशक, कय	मुख्य निदेशक, कय	सभी	महानिदेशक, बाय/संयुक्त सचिव ।

अनुसूची

भाग II— साधारण केन्द्रीय सेवा, बर्ग-4

पद विवरण		विद्युक्ति-प्राधिकारी			शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (प्रानुशासनिक-प्राधिकारी) और शास्तियां जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 के पद संख्याओं के संवर्ध में)	अपील-प्राधिकारी
		प्राधिकारी		शास्तियां		
1	2	3	4	5		
मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी का कार्यालय, मई दिल्ली ।						
सभी पद	उपमुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी	उपमुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी	सभी	मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी		
वेतन तथा लेखाअधिकारी का कार्यालय, मुंबई/कलकत्ता/मद्रास ।						
सभी पद	वेतन तथा लेखा-अधिकारी	वेतन तथा लेखा-अधिकारी	सभी	मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी ।		
शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय, मई दिल्ली ।						
सभी पद	प्रशासनिक-अधिकारी	प्रशासनिक-अधिकारी	सभी	मुख्य निदेशक		

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय सार्वजनिक संस्थान, कानपुर ।				
सभी पद	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सभी	निदेशक
क्षेत्रीय निदेशक (खाद्य) के कार्यलय, नई दिल्ली । संवर्द्ध । कलकत्ता । मद्रास (जिसमें अवशिष्टीय एक भी सम्मिलित है)				
सभी पद	सहायक निदेशक	सहायक निदेशक	सभी	उपमहानिदेशक (खाद्य) / क्षेत्रीय निदेशक (ख.द्य)
अनाज भण्डारकरण अनुसन्धान और प्रशिक्षण केन्द्र, हापुर ।				
सभी पद	सहायक निदेशक	सहायक निदेशक	सभी	निदेशक
भारतीय अनाज भण्डारकरण संस्थान, हापुर (जिसमें बाहर के एक भी सम्मिलित है)				
सभी पद	प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	सभी	परियोजना समन्वयकर्ता
उप-तकनीकी सलाहकार और उसके अधीन के एकक ।				
सभी पद	उप-तकनीकी सलाहकार	उप-तकनीकी सलाहकार	सभी	कार्यपालक निदेशक
रक्षा विभाग के लिए पिसाई चाय करार के भारसाधक अधिकारी का कार्यालय ।				
सभी पद	मुख्य निदेशक, क्रय	मुख्य निदेशक, क्रय	सभी	महानिदेशक, खाद्य/ संयुक्त सचिव ।

[सं. सं. 11012/1/70-ए.बी.पु.]

भार० एस० गुप्ता, उप-सचिव ।

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS
(Department of Mines & Metals)

New Delhi, the 13th January 1971

S.O. 636.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel) No. S.O. 72, dated the 29th December, 1958, under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired lands measuring 314 acres and the rights to mine, quarry,

bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 592.75 acres in village Sael, Thana Ramgarh, District Hazaribagh;

And whereas Sarvashree Annu Sahu, s/o Raghunath, Teju Sahu, Nakul Sahu and Gokul Sahu s/o Raju Sahu, Prabhu Sahu and Sarju Sahu ss/o Gobardhan, Dasrath Sahu and Sukhdco ss/o Arghu Sahu of village Seal, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, the interested persons have, under section 13 of the said Act, preferred their claims for compensation for acquisition of lands measuring 3.36 acres which form part of their lands so acquired, before the competent authority;

And whereas the amount of compensation offered by the competent authority has been accepted by the said claimants under protest due to its inadequacy and there is also a dispute as to the person or persons entitled to receive the compensation for an area of 0.55 acres of plot Nos. 160 and 171 between the claimants and the Forest Department, Government of Bihar.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi for the purpose of determining the amount of compensation and the person or persons entitled to receive the compensation for the lands referred to above.

[No. F. C3-5(3)/70.]

पट्टी नं० ६३६—य कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957

(वन और भूत विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1970

पट्टी नं० 636—य कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय (खान और इंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 72, तारीख 29 दिसम्बर, 1958 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने जिला हजारी बाग, थाना रामगढ़ के ग्राम साइल में 314 एकड़ माप की भूमि को, और 592.75 एकड़ माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने खोदने, के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकार अर्जित किए हैं ;

और यतः जिला हजारीबाग, थाना रामगढ़, ग्राम साइल के सर्व श्री अन्नू साहू सुपुत्र रघुनाथ, तेज साहू, नकुल साहू और गोकुल साहू सुपुत्र राजू साहू, प्रभु साहू और सरजू साहू सुपुत्र गोवर्धन, दशरथ साहू और सुख देव सुपुत्र आरधू साहू ने जो हितवद्ध व्यक्ति हैं, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 3.36 एकड़ माप की भूमि के, जो इस प्रकार अर्जित भूमि का भाग है, अर्जन के लिए प्रतिकारार्थ अपने दावे सक्षम प्राधिकारी को किए हैं ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्थापित प्रतिकर की राशि की अपर्याप्तता के कारण उक्त दावेदारों द्वारा वह राशि सविरोध ही स्वीकार की गई है और प्लॉट संख्याएं 160 और 171 के 0.55 एकड़ के क्षेत्र के लिए प्रतिकर पाने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में दावेदारों तथा बिहार सरकार के वन विभाग के बीच विवाद भी है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त निवशित भूमि के लिए प्रतिकर की राशि और प्रतिकर पाने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे ।

[सं० का० को० 3-5 (8)/70]

S.O. 637.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the later Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel) No. S.O. 72, dated the 29th December, 1958 under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired lands measuring 314 acres and the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 592.75 acres in village Sael, Thana Ramgarh, District Hazaribagh;

And whereas Late Barhan Mahto of village Sael, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, the interested person, had under section 13 of the said Act, preferred his claim for compensation for acquisition of lands measuring 0.32 acre which form part of the lands so acquired before the competent authority;

And whereas the claimant Barhan Mahto died leaving behind his sons and widow as heirs and a dispute for apportionment of compensation has arisen between his heirs Jugal Mahto, Dwarika Mahto, Mahra Mahto and his widow Dasu Devi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the apportionment of compensation payable to the claimants.

[No. F.C3-5(8)/70.]

प्रा० ७१० 637.—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय (खान और इंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 72, तारीख 29 दिसम्बर, 1958 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने जिला हजारीबाग, थाना रामगढ़ के ग्राम साइल में 314 एकड़ माप की भूमि को, और 592.75 एकड़ माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान क्रिया, बोर करने, खोदने के लिए और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, कार्य करने और ले जाने के अधिकारी अर्जित किए हैं ?

और यतः जिला हजारीबाग, थाना रामगढ़, ग्राम साइल के स्वर्गीय बरहान महतो ने जो हितवद्ध व्यक्ति है, उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.32 एकड़ माप की भूमि के, जो इस प्रकार अर्जित भूमि का भाग है, अर्जन के लिए प्रतिकरार्थ अपना दावा सक्षम प्राधिकारी को किया है ।

और अतः अपने पीछे पुत्रों और विधवा को उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ कर दावेदार बरहान महतो की मृत्यु हो गई और प्रतिकर के प्रभाजन के लिए उसके उत्तराधिकारी जुगल महतो द्वारिका महतो, महरा महतो और उसकी विधवा दासु देवी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दावेदारों को संदेय प्रतिकर के प्रभाजन को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री रबनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक आयुक्त, रांची होंगे ।

[सं० फा० सी 3-5(8)/70]

New Delhi, the 21st January 1971

S.O. 638.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel) S.O. No. 1123, dated the 2nd April, 1962, under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 9.80 acres (3.89 hectares) in village Religara, Thana Mandu, District Hazaribagh;

And whereas the Forest Department of the Government of Bihar through the Chief Conservator of Forests, Bihar, Ranchi, have under section 13 of the said Act, preferred their claim for compensation for acquisition of forest lands measuring 4.14 acres (1.68 hectares) and crops compensation thereof which form part of the lands so acquired to the competent authority;

And whereas there is a dispute as to the adequacy of the amount of compensation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri Rabaneshwar Prasad Sinha, Additional Judicial Commissioner, Ranchi, for the purpose of determining the amount of compensation payable to the said claimant.

[No. F. C3-13(13)/70.]

K. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1971

का० आ० 638.— यतः कोयला वाले क्षेत्र (वर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन, भारत सरकार के भूतत्पूर्व इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय (खान और इंधन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1128, तारीख 2 अप्रैल, 1962 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने जिला हजारीबाग, थाना मन्डु के रेलिगारा ग्राम में 9.60 एकड़ (3.89 हेक्टर) माप की भूमि को अर्जित किया है।

और यतः बिहार सरकार के वन विभाग ने वनों के मुख्य संरक्षक, बिहार, रांची के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 4014 एकड़ (1.68 हेक्टर) माप की वनभूमि और उस पर फसल अधिकार के, जो इस प्रकार अर्जित भूमि का भाग है, वर्जन के लिए प्रतिकराय अपना दावा सक्षम अधिकारी को किया है।

और यतः अधिकार क्षेत्री राशि की पर्याप्त के बारे में विवाद है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त दावदार को सदैव अधिकार की राशि को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है जिसमें श्री खनेश्वर प्रसाद सिन्हा, अपर न्यायिक प्रवक्ता, रांची होंगे।

[सं० फा० को० 3-13(13)/70]

के० सुब्रह्मण्यन, अवसर सचिव।

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 19th January 1971

S.O. 639.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. CBY 54 to CBY 20 in the Cambay Oil Field in Gujarat State, Pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

3. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, at Western Region, Shed No. 27, Makarpura Road, near Central Workshop, Baroda-4, the office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural Gas Commission), Baroda. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from Well No. CBY-54 to CBY-20

State : Gujarat

District : Kaira

Taluka : Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are.	P. Are.
Kodva	98	0	7	62
	70/Paiki	0	3	75
	24	0	9	87
	25	0	13	25
	69+70	0	40	87
	67	0	16	75
	66	0	3	75
Motipura	21	0	13	13
	22	0	4	27
	23	0	0	06
	26	0	12	12
	35	0	0	00
	41	0	5	40
	43	0	7	50
	43	0	15	75
	43	0	00	40
	V. P. Cart track	0	00	36
	109	0	00	70
	V. P. Cart track	0	2	43
	120	0	8	50
	119	0	4	40
	118	0	3	12
	117	0	8	37
	113	0	1	50
	115	0	5	92
	114	0	12	00
Neta	987	0	7	56
	988	0	3	75
Bhat Talawadi	93	0	12	81
	92	0	14	00
	V. P. Cart track	0	2	75
	37/2	0	4	56
	37/1	0	5	77
	38	0	4	21
	39	0	5	62
	40	0	6	62
	42	0	4	08
	43	0	9	87
	44	0	14	50
	25	0	28	00
	10	0	16	00
	8	0	6	87
	7	0	14	52
	5	0	8	75

[No. 11(1)/71-Lab & Legis.]

M. V. S. PRASADA RAU, Under Secy

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1971

का० आ० 639.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कम्बे तेल क्षेत्र में कुआं संख्या सी बी वार्ड-5, से सी बी वार्ड-20 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्तकि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग रोड नं० 27 मकरपुरा रोड, बरोधा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत: हो या किसी विधि व्यवहायी की मापतः।

अनसूची

कुआं संख्या सी बी वार्ड-5, से कुआं संख्या सी बी वार्ड-20 तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

राज्य—गुजरात

जिला—कर

तालूका—कम्बे

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	आर	पी आर
कोडवा	98	0	7	62
	70/पकी	0	3	75
	24	0	9	87
	25	0	13	25
	69-70	0	49	87
	67	0	16	75
	66	0	3	75
मोतीपुरा	21	0	13	13
	22	0	4	37
	23	0	0	06

	(1)	(2)	(3)
36 . . .	0	11	12
35 . . .	0	5	62
41 . . .	0	7	50
43 . . .	0	15	75
42 . . .	0	00	40
बी पी कार्ट ट्रैक . . .	0	00	56
109 . . .	0	00	70
बी पी कार्ट ट्रैक . . .	0	1	43
120 . . .	0	8	50
119 . . .	0	4	40
118 . . .	0	3	12
117 . . .	0	8	37
113 . . .	0	1	50
115 . . .	0	5	92
114 . . .	0	12	00
नगरा 987 . . .	0	7	56
988 . . .	0	3	75
भात सलवाड़ी 93 . . .	0	12	81
92 . . .	0	14	00
बी पी कार्ट ट्रैक . . .	0	2	75
37/2 . . .	0	4	56
37/1 . . .	0	5	77
38 . . .	0	4	31
39 . . .	0	5	62
40 . . .	0	6	62
42 . . .	0	4	08
43 . . .	0	9	87
44 . . .	0	14	50
25 . . .	0	26	00
10 . . .	0	16	00
8 . . .	0	6	87
7 . . .	0	14	52
5 . . .	0	8	75

[संख्या 11(1)/71-लेबर एण्ड लेजिस

म० वे० शिव प्रसादराव, प्रवर सचिव

(DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS)

(P. & T. Board)

New Delhi, the 23rd January 1971

S.O. 640.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director-General, Posts & Telegraphs, hereby specifies the 20th February, 1971 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Abohar Telephone Exchange, Punjab Circle.

[No. 5/3/71-PHB(3).]

D. R. BAHU,
Assistant Director General (PHB).

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1971

का० धा० 640.—स्थायी आदेश क्रम संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गए 1951 के भारतीय तार नियमों के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने अबोहर टेलीफोन केन्द्र में 20-2-71 से प्रस्तावित दर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है।

[संख्या 5-3/71-पी० एच० बी० (3)]

डी० आर० बाहु.

सहायक महानिदेशक पी० एच० बी०।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 19th January 1971

S.O. 641.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 5, read with section 9, of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4163, dated the 12th November, 1968, namely:—

In the said notification, under the heading "II Representatives of Employers", for entry (1), the following entry shall be substituted, namely:—

"(1) Shri K. S. K. Rao, Assistant Commissioner (Land Reclamation), Department of Agriculture, New Delhi.

[No. LWI. 1-6(23)/WE(MW).]

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

अ. रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(अ. और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी 1971

का० धा० 641.—स्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के अम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (अम

और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० कां आ० 4163 तारीख 12 नवम्बर 11 8 में और याग निम्नलिखित संशोधन करती है, यथावि :—

उक्त अधिसूचना में “11 नियोजकों के प्रतिनिधि” शीर्षक के नीचे प्रविष्टि (1) के धान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1) श्री के० एस० के० राव,
सहयक आयुक्ता (भूमि सुधार)
कृषि विभाग
नई दिल्ली ।

[स० एल० डब्ल्यू० आई-1-6 (23)/68-डब्ल्यू० ई०-(एम०डब्ल्यू०)]

हंस राज छावड़ा, भवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 22nd January 1971

S.O. 642.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of South Golukdih Colliery, Post Office Jharla, Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3)
AT DHANBAD

REFERENCE No. 92 of 1969

PRESENT:

Sri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the South Golukdih Colly.

Vs.

Their workmen.

APPEARANCES:

For employers—Sri P. C. Sharma, Superintendent of Collieries.

For workmen—Sri H. N. Singh, Vice-President, Koyala Ispat Mazdoor Panchayat.

INDUSTRY: Coal.

STATE: Bihar.

Dhanbad, dated the 7th of January, 1971

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of South Golukdih Colliery, Post Office Jharla, Dhanbad, and their workmen, by its order No. 2/107/69-LRII, dated the 2nd of December, 1969 referred to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below:—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of South Golukdih Colliery in reversioning its workman Shri Mathura Singh from the job of Fan Khalasi with effect from 16th December, 1968, was justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. The employers filed their written statement on 15th April, 1970 and the Union filed written statement on 11th August, 1970 on behalf of the workmen. But it is unnecessary to state the respective cases of the parties because the matter has been settled amicably between the parties through compromise.

3. On 4th January, 1971, a joint petition of compromise, duly verified by Sri P. C. Sharma, Supdt. of Collieries for and on behalf of the employers and by Sri H. N. Singh for and on behalf of the workman, has been filed and the parties have prayed that the award may be made in terms thereof.

4. According to the terms of compromise Sri Mathura Singh shall be paid 30 days sick leave for the period in 1968 and he will be paid full quarterly bonus for the quarters ending December, 1968, March, 1969 and June, 1969 as if he has worked on all these days. The continuity of service of Sri Mathura Singh will not be interrupted due to this stoppage of work with effect from 16th December, 1968 to 20th May, 1969.

5. The terms of the compromise are fair and reasonable and are accepted. Accordingly I pass an award in the terms of the joint petition of compromise, a copy of which is annexed with the award as annexure 'A'.

6. This may now be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,
Presiding Officer.

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. (3), DHANBAD

REFERENCE No. 92 OF 1969

Between the employers in relation to the South Golukdih Colliery of M/s. South Golukdih Coal Co. P.O. Jharia, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen Shri Mathura Singh, Fan khalasi represented by the Koyala Ispat Mazdoor Panchayat, P.O. Jharia, Dist. Dhanbad.

In the mutual interest, goodwill and industrial peace, the parties have decided to compose of this dispute on the following terms and conditions:

Terms of Settlement

- (1) That Shri Mathura Singh will be paid 30 days sick leave for the period in 1968.
- (2) That Shri Mathura Singh will be paid full quarterly bonus for the quarters ending December, 1968, March, 1969 and June, 1969 as if he has worked on all these days.
- (3) That the continuity of service of Shri Mathura Singh will not be interrupted due to this stoppage of work with effect from 16th December, 1968 to 20th May, 1969.

It is, therefore, prayed that the Tribunal be pleased to give the Award in terms of the settlement arrived at between the parties.

And for this, the parties shall ever pray.

On behalf of the management.
(Sd.) P. C. SHARMA, Supdt. of Collieries.
South Golukdih Coal Co.
South Golukdih Colliery, Jharia.

On behalf of the workman.
(Sd.) H. N. SINGH, Vice President:
Koyala Ispat Mazdoor Panchayat.
Jharia.

[No. 2/107/69-LR.II.]

Dated the 4th January 1971.

S.O. 643.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Katras Choituidih Colliery of Messrs Burrakar Coal Company Limited, Post Office Sijua (Dhanbad) and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3)
AT DHANBAD

REFERENCE No. 39 1970

PRESENT:

Shri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to Katras-Chottudih Colliery.

Vs.

Their workmen.

APPEARANCES:

For employers—Sri A. K. Chatterjee, Agent Katras Colliery.

For workmen—Sri Anant R. Sharma, Secretary, Bihar Koyala Mazdoor Sabha.

INDUSTRY: Coal.

STATE: Bihar.

Dhanbad, dated the 6th of January, 1971

AWARD

1. The Central Government, being of opinion that an industrial disputes exists between the employers in relation to the management of Katras Chottudih Colliery of Messrs Burrakur Coal Co. Limited, Post Office Sijua (Dhanbad) and their workmen, by its order No. 2/51/70-KR.II, dated the 14th of August, 1970 referred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below:

SCHEDULE

"Whether the management of Katras Chottudih Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, rendered Shri Yakub Milan, Mechanical fitter idle with effect from the 15th October, 1968 to the 23rd October, 1968? If so to what relief is the workman entitled?

2. Employers filed their written statement on 16th September, 1970. The Union did not file their written statement. However, this is of little consequence since the matter has been settled amicably between the parties through compromise.

3. The parties have filed a joint petition of compromise which has been verified by Sri A. K. Chatterjee, Agent, Katras Colliery for and on behalf of the Employers and by Sri Anant R. Sharma, Secretary of the Union for and on behalf of the workmen, and prayed that the award may be made in terms thereof.

4. According to the terms of the compromise the Employers have agreed to pay and the workman concerned and his trade Union have agreed to accept four day's wages for the period in question, namely, 15th October, 1968 to 23rd October, 1968 inclusive of one Sunday on 20th October, 1968 without prejudice to the submission made by the employers in their written statement dated 14th September, 1970.

5. It has been further agreed by the parties that the said payment shall be in full and final settlement of all the alleged claims of the workman concerned arising out of the present reference, and that the remaining period of four days excluding the intervening Sunday shall be treated, as an ex-gratia measure, as leave without wages and the said payment shall be made in the office of the colliery on or before 8th January, 1971.

6. It has been declared by the concerned workman and his aforesaid trade union that they have no subsisting dispute with the management in the matter of the present reference which stands fully and finally disposed of by this settlement and the parties shall bear their own costs of these proceedings.

7. The terms of compromise are fair and reasonable and are accepted. Accordingly I pass an award in the terms thereof and a copy of the aforesaid compromise petition is annexed with the award as annexure 'A'.

8. This may now be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,
Presiding Officer.

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3, DHANBAD

REFERENCE No. 39 of 1970

Employers in relation to Katras-Choitodih Colliery.

Vs.

Their workmen.

Terms of Settlement

4th January 1971

The parties aforesaid respectfully beg to submit as under:—

1. Without prejudice to the submissions made by the employers in their written statement dated 14th September, 1970, they have agreed to pay and the workman concerned and his trade union, the Bihar Koyla Mazdoor Sabha, have agreed to accept four days' wages for the period in question, namely, 15th October 1968 to 23rd October 1968 inclusive of one Sunday on 20th October, 1968.

2. It is further agreed by the parties that the said payment shall be in full and final settlement of all the alleged claims of the workman concerned arising out of the present reference.

3. It is further agreed that the remaining period of four days excluding the intervening Sunday shall be treated, as an ex-gratia measure, as leave without wages.

4. The said payment shall be made in the office of the colliery on or before 8th January, 1971.

5. The workman concerned and his aforesaid trade union declare that they have no subsisting dispute with the management in the matter of the present reference which stands fully and finally disposed of by this settlement.

6. The parties shall bear their own costs of these proceedings.

7. The parties pray that the Tribunal may be pleased to accept this settlement on record and to give its award in terms thereof.

1. (Sd.) ANANT R. SHARMA, Secy.

(Sd.) A. K. CHATTERJEE, Supdt.

Bihar Koyla Mazdoor Sabha.

Jharla West.

2. (L.T.I.) YAKUB MIA.

Workman concerned:

For Workmen.

For employers.

Dated 4th January, 1971.

[No. 2/51/70-LR.II.]

New Delhi, the 29th January 1971

S.O. 644.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Banalee Colliery, Post Office, Nandi, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No 49 OF 1970

PARTIES:

Employers in relation to the management of Banalee Colliery.

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Shri K. P. Mukherjee, Advocate.

On behalf of Workmen—Shri Ramen Banerjee, Advocate.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. 6/55/70-LRIL, dated October 27, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Benalee Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

- "(1) Whether the management of Benalee Colliery, Post Office Nandi, District Burdwan was justified in declaring a lock-out with effect from the 6th August, 1970 and continuing the same upto the 28th August, 1970?
- (2) Whether the action of the management of Benalee Colliery, Post Office Nandi, District Burdwan in declaring a closure of the colliery with effect from the 29th August, 1970 as per their notice dated the 26th August, 1970 is legal and justified?
- (3) To what relief are the workmen entitled to in the two cases above?"

2. It is an admitted fact that the Benalee Colliery is owned by Nimecha Coal Company Limited (hereinafter referred to as the company). According to paragraph 2 of the written statement filed by the company:

"There is no exclusive Trade Union of the workmen employed at the said Benalee Colliery. From time to time, several Trade Unions of workmen of different collieries purported to represent the workmen of Benalee Colliery resulting inter-trade union rivalries of which the workmen were made victims from time to time causing dislocations of the normal day-to-day work at the Colliery. Prior to December, 1969 a large number of workmen employed at the said Benalee Colliery were represented by a Trade Union connected with Sanjukta Socialist Party. Subsequent to December, 1969, another Trade Union having affiliation with Communist Party of India (Marxist) purported to represent a section of the workmen and there were inter-trade-union clashes between the supporters of the above mentioned two trade unions. Colliery Mazdoor Sabha, Asansol, affiliated with the Communist Party of India purported to represent some of the workmen which resulted further inter-trade-union clashes amongst the different Trade Unions purporting to represent the workmen employed at Benalee Colliery. As a result of such violent clashes due to inter-trade-union rivalries there were serious criminal assaults at the colliery on the 21st February, 1970 which continued thereafter and on 25th February, 1970 due to such violent clashes four persons were killed and several other persons seriously injured. Under such grave circumstances as well as compelling reasons the company had no other alternative but to close down with effect from 26th February, 1970 until further notice the said Benalee Colliery and notified to the workmen accordingly by its Notice dated 25th February, 1970."

This notice is Ex. 1 and the relevant portion of it is set out below:

"In view of the fact that serious labour unrest is prevailing both inside and outside of the premises of the Benalee Colliery and in view of the fact that certain workmen have been killed and several others injured and in view of the fact that the lives of Staff and Officers are unsafe under the above circumstances, the Management hereby notifies that considering the gravity of the situation the Management is compelled to close down the Mine with effect from 26th February, 1970 till further notice." (Underlined by me).

Now, a closure "till further notice" is not really a closure of business. It amounts to a temporary suspension of business. I am not, however, concerned with that closure in this reference.

3. In paragraph 3 of the written statement filed by the Company it was pleaded:

"That due to continued uneconomic working and financial losses relating to the running of the said Benalee Colliery, it was necessary during the relevant period for the Company to reorganise its working at the said Colliery. Further, on account of depletion of the working reserves in Bogra seam and the shortage of working faces at Satgram seam at the Benalee Colliery, the Company had in employed during the

relevant period large number of surplus hands but was unable to take necessary steps to retrench some of such surplus hands on account of the continued unlawful and subversive activities at the said Benalee Colliery and/or apprehensions of further troubles at the Colliery. Such continuance of employment of large number of surplus hands at the Benalee Colliery further adversely effected the working and raising at the Colliery and continued financial losses for the company. In this view of the matter of the Company it was necessary to take a final decision to retrench some of such surplus hands in order to avoid further financial losses to the Company and accordingly the Company retrenched 71 workmen with effect from 1st August, 1970 and took necessary steps in accordance with the law relating to the payments in terms of Section 25F of the Industrial Disputes Act to the said retrenched workmen."

The workmen replied by resorting to strike with effect from 3rd August, 1970, described as illegal strike by the Company. The Company warned the workmen that the strike was illegal and unjustified and that the same should be called off immediately. It was further notified that the workmen would not be entitled to any wages for the strike period. The notice sent to the workmen is Ex. 3. According to the Company, the notice had little effect upon the workmen. It was further pleaded by the Company that the workmen aggravated the situation by an illegal stay-in strike and unlawful occupation inside the mine. Thereupon, the Company sent to the workmen another notice, dated August 5, 1970, Ex. 7, stating, inter-alia.

"In the circumstances, it is notified to all such workmen who are in unauthorised occupation of the mines to immediately vacate the mines, as otherwise, the management shall be compelled to take necessary steps so that the workmen may not continue to violate the safety provisions relating to the mines. It has been further reported that in order to excite the workmen, few of such workmen who are on strike are threatening to launch simultaneously hunger-strike.

In case the management is compelled to take such action, the workmen who are continuing such stay-in-strike and having unauthorised occupation of the mines, as stated above, shall be entirely responsible.

The management, however, hopes that good sense would prevail amongst the workmen concerned and they would resume their respective duties immediately and call off such stay-in-strike. It is further notified to all workmen concerned that in case such strike is not called off immediately, the management may be compelled to take necessary actions without any further reference for which all workmen concerned shall be held responsible.

As already notified to the workmen concerned, the management reminds the workmen that they will not be entitled to any wage for the strike period."

In paragraph 7 of the written statement, the Company pleaded:

"That in view of the grave situation prevailing at the Colliery along with various subversive activities including unauthorised occupation by a section of workmen inside the mine, continued violations of the Mines Safety regulations and other relevant factors as stated in the various notices issued from time to time to the workmen concerned, the Company had no other alternative but to take a decision to declare a lock-out of the said Benalee Colliery. Accordingly, by a notice dated the 6th August, 1970, the Company declared a 'lock-out' of the said Benalee Colliery at 4 P.M."

The notice of lockout, dated August 6, 1970, is Ex. 8 and the material portion of the same is set out below:

"The Company hereby notifies to all workmen and employees employed at the Benalee Colliery that inspite of our earlier notices dated the 3rd, 4th 5th and 6th instant, the illegal and unjustified sudden stay-in-strike continued since the 3rd August 1970 along with various subversive activities including unauthorised occupation by a section of workmen who are on strike.

The Company further notifies that for the reasons stated in the above mentioned several notices which are to be treated as part of the present notice of lock-out and as a consequence of the illegal stay-in-strike by workmen employed on the surface as well as inside the Mines

since the 3rd August, 1970 the Company is compelled to declare lock out with effect from 4 P.M. of 6th August 1970 until further notice and restoration of normal peaceful working condition and assurance as well as undertakings by the workmen to maintain strike discipline.

All workmen concerned are further notified that as stated in our earlier notice, the workmen concerned shall not be entitled to any wage and/or salaries during the period of the present lock out.

In view of the provisions of the Mines Act and the Regulations framed thereunder the workmen employed in the essential services shall, however, not be affected by the present notice of lockout but shall continue to attend their respective duties during the period of such lock out."

In spite of lockout, the unlawful activities on the part of the workmen were alleged to continue and thereupon it was pleaded in paragraph 12:

"That as the unlawful activities on the part of the workmen concerned continued, the company for the reasons stated in its notice of closure dated 28th August, 1970 declared complete closure of Benalee Colliery with effect from 29th August, 1970."

The notice of closure is Ex. 13 and is set out hereinbelow:

"For the reasons stated in the enclosed notice the Benalee Colliery is closed down completely, with effect from the 29th August, 1970, and as a consequence of such closure your employment is hereby terminated, with effect from the date of closure, viz., the 29th August, 1970. As the above-mentioned closure is due to the unlawful activities of the workmen themselves and the situation created by them, they are not entitled to any compensation under the provision of Chapter VA of the Industrial Disputes Act, 1947, and in the circumstances you are also not entitled to such compensation.

You alongwith other workmen will be notified in due course about other payments.

Your are required to vacate your quarters, if any, occupied by you, within three days from the date of this letter."

In paragraph 14 of the written statement it was stated that steps for payment of legal dues to the workmen, whose services stood terminated on account of the closure of the Colliery, were taken subsequent to the closure on August 29, 1970. Also steps were taken to remove the machinery, equipment, haulage pump, etc., from the Colliery to give effect to the closure. Due to continued obstruction by the workmen little progress was made in this respect.

4. This is in short the summary of the written statement filed by the management, except that there was a preliminary objection taken to the effect that on account of the closure of the Colliery the reference as made was not maintainable on merits.

5. A trade union of the name of Colliery Mazdoor Sabha espoused the cause of the workmen and filed a written statement. In paragraph 2 of the written statement the trade union claimed to have in its fold the majority of the workmen of the Colliery and further claimed to function in the Colliery since January, 1970. According to the said written statement, the Company was all along depriving the workmen of their legitimate dues, for example, leave wages, railway fares, lead and lift, sick leave, etc. and also refusing to implement the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry. The trade union took step for redress of such unfair labour practice on the part of the Company. The Company did not entertain the demands but tried to thwart them and at last declared an illegal lock-out of the Colliery on and from February 25, 1970. The trade union raised an industrial dispute over this illegal lockout by the company and, according to the pleading, the Company was compelled to lift this lockout on certain terms. Thereupon, negotiations started in order to arrive at a settlement but the Company frustrated the negotiations, at first by retrenching 62 workmen who were members of the trade union with effect from July, 27, 1970 and, there after, on being prohibited from doing so by the Regional Labour Commissioner (C), Asansol, by issuing notices of retrenchment of 71 workmen with effect from 1st August, 1970. When the conciliation was taken up in respect of second dismissal, the Company, it was alleged, illegally and wrongfully locked out the Colliery with effect from August 6, 1970. When the workers led by the trade union demonstrated, the Company lifted the lockout, allowed the workmen to rejoin and soon thereafter issued notice of closure of the colliery with effect from August 29, 1970.

The workmen alleged that no payment were made to them under Section 25FFF of the Industrial Disputes Act. It was also alleged that the closure was a mere purported closure and amounted to no closure at all.

6. Bearing in mind the pleadings as summarised hereinbefore, I have to answer the reference as made before this Tribunal.

7. I first take up for consideration the preliminary objection urged on behalf of the Company, with which the second issue referred to this Tribunal is so closely linked up that the two should not be severed. The preliminary objection was that since the business of Benalee Colliery stood closed down, no industrial dispute in respect of a closed business could come within the purview of Industrial Tribunals. Now, it is settled law that where a business has been closed and it is either admitted or found that the closure is real, any dispute arising with reference thereto would not fall within the purview of the jurisdiction of Industrial Disputes Act and that will a fortiori be so, if a dispute arises—if such can be conceded after the closure of the business between a quondam employers and employees. In the case of India Hume Pie Co. Ltd., vs. their Workmen, 1969, 1 LLJ 242(245), the Supreme Court further observed:

"In our opinion, it was not open to the tribunal to go into the question as to the motive of the appellant in closing down its factory at Barakar and to enquire whether it was *bona fide* or *mala fide* with some oblique purpose, namely, to punish the workmen for the union activities in fighting the appellant. It has been laid down by this Court in a series of decisions that it is not for industrial tribunals to enquire into the motive to find out whether the closure is justified or not." (Underlined by me).

The only question that can be urged with regard to the closure is whether the closure is a real one or a purported or a sham closure. To that limited extent, I may consider the second issue referred to this Tribunal by the order of the reference. On the point whether the closure was a real or sham, there was one witness examined on behalf of the workmen. That witness was Sunil Sen, Organising Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha. In answer to a question put by the Tribunal he said:

"I have not seen them raising coal. I have seen Chaprasis and guards working on the surface and I have also found the pump khalasis and Sardars going down the mine. What I mean to say is that only essential workmen were instructed to go on with their work. But other workmen were not essential and were not instructed to go on working. I dispute such workmen ceased to work after a couple of months after closure."

Further, in cross-examination he said:

"Excepting essential work no work was being carried on in the Colliery after August 29, 1970. I know that in November, 1970 large quantities of surface materials have been removed from the Colliery."

From the above evidence, it cannot be held that the closure was a sham closure or a purported closure. Even after a business is closed, some steps must necessarily be taken in order to safeguard the property. Some essential staff must also be kept employed in order to see that the mines do not become flooded or the Colliery seems do not catch fire or stock-in-trade may not deteriorate due to ravages of nature and of men. The fact that large quantities of surface materials were being removed from the Colliery, as stated by the witness for the workmen, indicates that the Colliery was in the process of liquidation. There was one witness examined on behalf of the employers. That witness was Biman Kantl Bagchi, Superintendent of Collieries. He does not appear to be a very well informed witness because he himself confessed, "I have not been able to give the correct version". He, however, stated in course of cross-examination:

"It is not true that the Benalee Colliery office is still functioning. The office is completely closed. After closure some essential workmen were maintained to guard the materials on the surface and to save the materials underground. So far as I remember such workmen continued to be employed for two months after the date of closure.

To Tribunal

Now the properties are lying unguarded.

Cross-exam. contd.

Ques: Are the essential services necessary to maintain the coal seams unmanned now?

Ans: I am not clear about what is meant by the expression maintaining the coal seams'.

Since the working has been discontinued, it is not necessary to maintain workmen to see that roofs do not cave in. It is not necessary to maintain underground power supply. At present we are not maintaining any electric lighting staff. At present nobody is looking after the electric connections. The bungalows are now vacant and the officers are not putting up there. In the colliery area however there is some lighting. Nobody, however, is maintaining that. The services of workmen employed to look after essential services were not terminated by notice. They were temporary workmen."

From the evidence I am convinced that the business in the Colliery has really stopped. That being the position I am not further concerned with the motive that was behind the closure.

7. There is another aspect of the matter to which I need refer. It was urged on behalf of the workmen that even if the closure was real, the same was not legal because before the closure the workmen were not paid their dues in accordance with Section 25FFF of the Industrial Disputes Act. Now, Section 25FFF in so far as it is material for the purpose is set out hereinbelow:—

"25FFF(1). Where an undertaking is closed down for any reason whatsoever, every workman who has been in continuous services for not less than one year in that undertaking immediately before such closure shall, subject to the provisions of sub-section (2), be entitled to notice and compensation in accordance with the provisions of Section 25F, as if the workman had been retrenched:

Provided that where the undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer, the compensation to be paid to the workman under clause (b) of Section 25F shall not exceed his average pay for three months.

Explanation—An undertaking which is closed down by reason merely of financial difficulties, (including financial losses) or accumulation of undisposed of stocks (or the expiry of the period of the lease or the licence granted to it where the period of lease or licence expires on or after the first day of April, 1967) shall not be deemed to have been closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer within the meaning of the proviso to this sub section."

On a plain meaning of the section it appears that in order to entitle a workman to claim compensation under this Section, two conditions must be fulfilled, (i) closure and (ii) one year's continuous service by the concerned workman. If these two conditions co-exist, at the time of the closure, the workmen whose services are terminated on such closure, become entitled to notice under Section 25F and compensation also according to Section 25F. At the same time, the plain reading of Section 25FFF(1) is that the right of notice and compensation for termination of employment flows from closure of the undertaking but the section does not seek to make closure effective upon payment of compensation and upon service of notice or payment of wages in lieu of notice. An employer proposing to close his undertaking may serve notice of termination of employment: if he fails to do so, he becomes liable to pay wages for the period of notice. Therefore, non-payment of compensation or non-service of notice will not make the closure bad but may merely clothe the workmen with right of compensation at certain rates. To what amount the workmen will be entitled, in the instant case, I shall deal with while dealing with issue No. 3 referred to this Tribunal.

8. In the result, I hold that the action of the management of Benalee Colliery in declaring a closure of the Colliery with effect from 29th August, 1970, as per notice dated the 28th August, 1970 was legal and justified.

9. I now turn to the first issue referred to this Tribunal, namely, the justifiability of declaring a lock-out with effect from August 7, 1970 and continuing the same upto August 28, 1970. The justification for the lock-out, as given in the notice (Ex.8), were: (a) stay-in strike, (b) refusal to withdraw the strike in spite of repeated notices from the management (c) 'various subversive activities'

including unauthorised occupation of the underground portion of the mine by a section of the workmen, who were on strike. The version as given in the notice was disputed by the sole witness examined by the workmen, namely, Sunil Sen, in the following language:

"....workers in the colliery struck work by way of protest. The strike was withdrawn at the request of the Regional Labour Commissioner on 5th August, 1970. When the workmen reported for duty on the 6th, the management refused to employ them excepting those who were members of the essential staff. The workmen took up the matter before the Conciliation officer and learnt from the Conciliation officer that there had been a lockout declared in the colliery."

He further said in course of his examination in-chief:

"The conciliation proceedings failed. On August 29, 1970 the dispute over lockout was pending before the Conciliation Officer. After the 29th August, 1970 I have found large number of workmen working at Benalee colliery."

The version as told by workmen's witness, if it had been true, would have, in the ordinary course of events, caused a demand by the workmen before the management for immediate employment. In answer to questions put by the Tribunal the workmen's witness Sunil Sen replied:

"On the 7th, I myself along with some workmen approached Mr. Bagchi, the Manager, with the request that the workmen should be allowed to resume their duties. He replied that he was unable to say anything. Thereafter we did not write any thing to the Directors of the Company or the authorities above Mr. Bagchi. We straight away approached the Regional Labour Commissioner with a written request. The industrial dispute over refusal to give employment was never formally or informally taken up with the management excepting that we spoke to Mr. Bagchi."

This is somewhat extra-ordinary conduct. What is more, such a conduct on the part of the workmen does not supply a footing for an industrial dispute. In case of *Sindhu Resettlement Corporation Ltd. vs. Industrial Tribunal, Gujarat*, (1968) 1 LLJ 834 the Supreme Court observed:

"An industrial dispute, as defined, must be a dispute between employers and employers, employers and workmen and workman and workman. A mere demand to a Government without a dispute being raised by the workmen with their employer cannot become an industrial dispute. Consequently, the material before the tribunal clearly show that no such industrial dispute, as was purported to be referred by the State Government to the tribunal ever existed before Appellant Corporation and the Respondent, and the State Government in making the reference obviously committed an error in basing its opinion on material which was not relevant to the formation of opinion."

Be that as it may, I am not impressed by the version as spoken by the sole witness for the workmen. The strike as referred to by the management was not disputed in fact. In paragraph 11 of the written statement filed by the workmen it was stated:

"assuming but not admitting that the demonstrations made by the workmen underground amounted to illegal strike within the meaning of the Industrial Disputes Act the said demonstrations were lifted and the workmen came out of the mine before the purported notice of lock-out was issued."

On the materials appearing before me, I am satisfied that there was justifiable ground for a lock-out. I need notice that it was nobody's case that the lock-out was otherwise bad under Section 22 of the Industrial Disputes Act.

10. I am now left with the third issue referred to this Tribunal, namely to what relief the workmen are entitled to in the two cases above. I have already held that the lock-out was justified and because it was precipitated by certain acts on the part of the workmen themselves, the employees were not entitled to receive any wages from the employers for the period of lock-out. So far as the period of closure is concerned, I find that the workmen were not given one month's notice in writing as contemplated under Section 25FFF(1) read with Section 25F(a). Therefore, the workmen became entitled to wages in lieu of notice. I further find that it is not the case of the management that the colliery was closed

down by reason merely of financial difficulty. Therefore, the explanation under Section 25FFF(1) was not attracted. I also find that the colliery was closed down under the main provision of Section 25FFF(1) exclusive of the proviso. Therefore, the workmen, who had been incontinuous service for not less than one year under the employer, would be entitled to compensation equivalent to 15 days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of 6 months.

11. Mr. K. P. Mukherjee, learned Advocate for the management, however, urged that I should not indicate the relief to which the workmen became entitled, because in a case of closure that was not within the purview of the jurisdiction of an industrial tribunal. In support of his contention he relied upon a decision of the Patna High Court, in *Hind Shipper (Private) Ltd., vs. Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad*, (1968) 1 LLJ, 365(1968) in which it was observed:

"The reference has been made in regard to compensation payable as a result of the closure and is based on a notification after the closure. It follows, applying the principle laid down in the decisions referred to above, that the reference itself was beyond the competence of the Central Government. The resultant award must, therefore, be held as void and the contention raised on behalf of the respondents must fail. The fact that the claim of the workmen concerned to a certain quantum of compensation was disputed by the management may have given rise to a dispute, but such a dispute, in my opinion, is precisely a matter which has to be investigated by the specified labour court under the provisions of Sub-sec.(2) of Sec. 33C of the Act and it does not lie in the competence of the appropriate Government to forge an additional remedy in such cases by making a reference under any of the Sub-clauses of S.10 of the Act."

I am not in this award going to calculate the amount to which the workmen were entitled. That is left to an application under Section 33C of the Industrial Disputes Act. I have merely indicated the principle of compensation which might be attracted on the basis of the findings made by me in this award.

This is my award.

Sd./
B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

Dated, January 12, 1971.

[No. 6/55/70-LRII.]

ORDERS

New Delhi, the 18th January 1971

S.O. 645.—Whereas, the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Chandrasekhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Singareni Collieries Company Limited in prescribing 7 A.M. to 1 P.M. underground and 3.30 P.M. to 5.30 P.M. surface as working hours to Sarvashri Neerla Lingaiah and Ganapurapu Rajam, Survey Mazdoors of No. 2 Incline or Belampalli Division is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?"

[No. 7/11/70-LRII.]

(अन्न और रोज़गार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1971

का० आ० 645.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्वय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड डाकघर कोटागुडम कोलियरीज (आन्ध्र प्रदेश) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7—क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी होंगे; जिनका मुख्यालय अफजल लोड, तिलक रोड, रामकोट, हैदराबाद-1 होगा और उक्त विवाद न्यायनिर्णयन के लिए उक्त औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या बेलम्पल्ली डिभिजन की सं० 2 इन्वलाइन के सर्वेक्षण मजदूर सर्वश्री नीरला लिंगेय्या और गानापुरा पुराजम के लिए 7.00 पूर्वाह्न से 1.00 अपराह्न भूमिगत और 3.30 अपराह्न से 5.30 अपराह्न तक सतह पर काम के घंटे निर्धारित करने की सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कमकर किस अनुसूची के हकदार हैं ?

[सं० 7/11/70—एल० आर० 2]

New Delhi, the 19th January 1971

S.O. 646.—Whereas, the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Belampalli (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Chandrasekhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

“Having regard to the nature of duties that are being performed by the following 18 Gang Mazdoors, whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Belampalli is justified in not giving Category IV wages to the said workers? If not, to what relief are the said workmen entitled and from what date?”

1. Mohammed Ankus.
2. B. Ramuloo.
3. P. Kondal Rao.
4. M. Moorthy.
5. Bondari Rajalingu.

6. G. Venkata Rao
7. Radrarap Arsiat.
8. Md. Yakoob.
9. K. Laxmirajam.
10. Ameer Khan.
11. F. Francis.
12. Mateti Lachamaiah
13. G. Nagulu.
14. Bingi Yenkatil.
15. K. Chandralah.
16. Charnappa.
17. Dosthi Mohad.
18. Anthoni.

[No. 7/9/70-LR.II.]

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1971

का० आ० 646.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, डाकघर लबेमपल्ली (आंध्र प्रदेश) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7—क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी होंग, जिनका मध्यालय अफ़्जल लौज, तिलक रोड, रामकोट, हैदराबाद-1 होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या निम्नलिखित 18 गैंग मजदूरों द्वारा किये जा रहे काम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सिगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, लबेमपल्ली के प्रबन्धतन्त्र का उक्त कर्मकारों को श्रेणी-4 की मजदूरी न देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ।”

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. श्री मोहम्मद अनकुस | 10. श्री अमीर खां |
| 2. श्री बी० रामूल | 11. श्री एफ० फ्रांसिस |
| 3. श्री पी० कोण्डल राव | 12. श्री मतेती लछमैया |
| 4. श्री एम० मूर्ति | 13. श्री जी० नागुलु । |
| 5. श्री गोंडारी राजालिंग | 14. श्री बिगी येकती |
| 6. श्री जी० बैकटा राव | 15. श्री के० चन्द्रैया । |
| 7. श्री रद्रारप अरियल | 16. श्री चरनाप्पा । |
| 8. श्री मोहम्मद याकूब | 17. श्री डोस्थी मोहद । |
| 9. श्री के० लक्ष्मीराजम् | 18. श्री अन्योनी । |

[सं० 7/9/70—एल० आर० 2]

S.O. 647.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Surendra East Loyabad Colliery, Post Office Kusunda, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Surendra East Loyabad Colliery, Post Office Kusunda, District Dhanbad in rendering Shri Kaleshar Beldar and Smt. Deorania Kamin, Wagon Loaders idle for the period from 3rd May, 1969 to 15th June, 1969 and 3rd May, 1969 to 17th June, 1969 respectively is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?”

[No. 2/119/70-LR.II.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

का० आ० 647.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाययुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सुरेन्द्रा ईस्ट लोयागढ़ कोलिअरी, डाकघर कुसुंदा, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची II

“क्या सुरेन्द्रा ईस्ट लोयागढ़ कोलिअरी, डाकघर कुसुंदा, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र की श्री कलेशर बेलदार और श्रीमती देओरानिया कामिन बैगन लोडरों को क्रमशः 3-5-69 से 15-6-69 और 3-5-69 से 17-6-69 की कालावधि के लिए बेकार करने को कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ।”

[सं० 2/ 119/70—एल० आर०-2]

करनैल सिंह, अवसर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 29th January 1971

S.O. 648.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 3272, dated the 5th August, 1969, the Central Government hereby exempts the Budge, Budge Installation and Paharpur Installation belonging to the Indian Oil Corporation Limited, from all the provisions of the said Act. for a further period of one year with effect from the 16th August, 1970 up to and inclusive of the 15th August, 1971.

[No. 601(31)/70-HI.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1971

का०आ० 48—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3272 तारीख, 5 अगस्त, 1969 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बजबज संस 199 और पहाड़पुर संस्थापन को उक्त अधिनियम के सभी उपबन्धों से 16 अगस्त, 1970 से 15 अगस्त, 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 601(31)/70-एच०आई]।

S.O. 649.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the factories mentioned in the schedule below in the State of Tamil Nadu in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period up to and inclusive of the 11th August, 1971 or until the enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

THE SCHEDULE

1. Special Maintenance Sub-Division Workshops Compound, Mettur Dam.
2. Meter and Relay Testing Section, Cross Cut Road, Coimbatore-12.
3. Meter and Relay Tests and Telephone Section, 8-81 East Main Road, Mettur Dam.
4. Udampalpet Sub-Section, Tiruppar Road, Udampalpet, Coimbatore District.
5. Special Maintenance Laboratory, Control Rooms & M.R.T. Section/Pasumalai, Tamil Nadu Electricity Board, Pasumalai, Madurai-17.
6. Papanasam Power House, Papanasam Project P.O., Tirunelveli District.
7. Special Maintenance Repair Shed, Cross Cut Road, Tatapad Coimbatore-12.
8. Hydro Electric Power Station 'A' Unit: Mettur Dam Power House and 'B' Unit, Mettur Tunnel Power House Post Box No. 4, Mettur Dam, (Post) Salem District.

[No. 602(33)/70-HI.]

का० आ० 649—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे की अनुसूची में वर्णित कारखानों की तमिलनाडु राज्य में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिवाय के सन्दाय से 11 अगस्त, 1971, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, तक की कालावधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हों, एतद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

1. विशेष अनुरक्षण उपखण्ड कर्मशाला प्रांगण, मेट्टूरडैम।
2. मीटर एवं रिले परीक्षण अनुभाग, क्रॉस कट रोड, कोयम्बटूर-12
3. मीटर एवं रिले परीक्षण और टेलीफोन अनुभाग, 8-81 ईस्ट मेन रोड, मेट्टूर डैम।
4. उदमालपेट उप-केन्द्र, तिरुप्पार रोड, उदमालपेट, जिला कोयम्बटूर।
5. विशेष अनुरक्षण प्रयोगशाला, नियंत्रण कक्ष और एम०आर०टी० अनुभाग/पसुमलाई, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, पसुमलाई, मदुराई-17।

6. पपनासम बिजली घर, पपनासम परियोजना डाकघर, जिला तिरुनेलवेली ।
7. विशेष अनुरक्षण मरम्मत शेड, फ्रास कट रोड, तातपद, कोयम्बटूर-12 ।
8. जल विद्युत बिजली घर (ए) यूनिट: मेटूर डैम बिजली घर और "बी" यूनिट, मेटूर सुरंग बिजली घर, पोस्ट बाक्स संख्या 4, मेटूर डैम (पोस्ट) जिला सलेम ।

[सं० फा० 602(33)/70-एच०आई०]

S.O. 650.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Government of India Press, Koratty, Trichur District (Kerala State), belonging to the Government of India are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees State Insurance Act, 1948, (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3339, dated the 8th August, 1969 the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from all the provisions of the said Act for a further period of one year with effect from the 6th July, 1970 up to and inclusive of the 5th July, 1971.

[No. 601(25)/70-HI.]

का० आ० 650—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि भारत सरकार के भारत सरकार मुद्रणालय, कोराट्टी, त्रिचुर जिला (केरल राज्य) के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के सारतः समरूप उपबन्धित स्वरूप प्रसुविधाएं अन्यथा प्राप्त हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3339 तारीख 8 अगस्त, 1969 के क्रम में केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने को उक्त अधिनियम के सभी उपबन्धों से 6 जुलाई, 1970 से 5 जुलाई, 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा छूट देती है ।

[सं० फा० 601(25)/70-एच०आई०]

S.O. 651.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Geodetic and Research Branch Workshop, Survey of India, Dehra Dun, belonging to the Government of India are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 364, dated the 22nd January, 1970 the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned workshop from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st January, 1971 up to and inclusive of the 31st December, 1971.

[No. 601(54)/70-HI.]

का० आ० 651.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि भारत सरकार के भूगणितय और अनुसंधान शाखा कर्मशाला, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के सारतः समरूप प्रसुविधाएं अन्यथा प्राप्त हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 364 तारीख 22 जनवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कर्मशाला को उक्त अधिनियम के प्रवृत्तन से 1 जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 601(54)/70-एच०आई०]

New Delhi, the 1st February 1971

S.O. 652.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Andhra Mercantile Agency, 5-9-77, Chapel Road, Gunfoundry, Hyderabad-1 including its branch at Governorpet, Vijayawada have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1969.

[No. 8/136/70-PF.II(i).]

नई दिल्ली, 1 फरवरी 1971

का० आ० 652.—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आन्ध्र मर्कैन्टाइल एजेंसी, 5-9-77 चैपल रोड, गनफाउण्ड्री, हैदराबाद-1 नामक स्थापन, जिसमें इसकी गवर्नरपेट, विजयवाड़ा की शाखा सम्मिलित है, से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के दिसम्बर, के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/36/70-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 653.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st December, 1969 the establishment, known as Messrs Andhra Mercantile Agency Chapel Road, Hyderabad including its Branch at Governorpet Vijayawada for the purposes of the said proviso.

[No. 8/136/70-PF.II(ii).]

आ० आ० 653.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्द्वारा मैसर्स आन्ध्र मर्कैन्टाइल एजेंसी, चैपल रोड, हैदराबाद नामक स्थापन, जिसमें इसकी गवर्नरपेट, विजयवाड़ा, की शाखा सम्मिलित है को 31 दिसम्बर, 1969 के उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 8/136/70-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 654.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Mysore State Federation of Consumers' Co-operative wholesale Stores Limited, Bangalore have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1970.

[No. 8/178/70/PF-II(1).]

क्रा० आ० 654—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसूर स्टेट फ़ेडरेशन आफ कन्ज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड, बंगलूर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहत हो गई है कि कमचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 मई के इक्कीसवें दिन को प्रवृत्त समझी जाएगी।

[संख्या 8/178/70/पी० एफ० 2(i)]

S.O. 655.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st May, 1970, the Establishment known as the Mysore State Federation of Consumers' Co-operative wholesale Stores Limited, Bangalore for the purposes of the said proviso.

[No. 8/178/70-PF-II(ii).]

क्रा० आ० 655—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मैसूर स्टेट फ़ेडरेशन आफ कन्ज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड, बंगलूर नामक स्थापन को 31 मई, 1970 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 8/178/70 पी एफ० 2(ii)]

S.O. 656.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs J. N. Roy Choudhury (Traders) Private Limited, 18, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1965.

[No. 8/132/70/PF.II.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

क्रा० आ० 656—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेर्स जे० एन० राय चौधरी (ट्रेडर्स) प्राइवेट लिमिटेड 18, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध

नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1965 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/132/70 पी० एफ० 2]

दसजीत सिंह, अव्वर सचिव।

(Department of Rehabilitation)
(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 15th January 1971

S.O. 657.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri R. K. Kapoor, Assistant Settlement Officer in the Office of the Regional Settlement Commissioner, New Delhi as Settlement Officer in the Office of the Regional Settlement Commissioner (Central) New Delhi for the purpose of performing the functions assigned to such officers by or under the said Act with immediate effect.

[No. 7/49/ARG/55-V-II.]

JANKI NATH, Settlement Commissioner (C)
Ex-Officio Under Secy. to the Govt. of India.

(पुनर्वासि मंत्रालय)

(मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली 15 जनवरी, 1971

का०आ० 657—विस्थापित व्यक्ति (मुआविजा तथा पुनर्वासि) अधिनियम 1954 (1954 के 44) के भाग 3 के अनुभाग (1) की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय—नई दिल्ली के श्री आर० के० कपूर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी को प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय) में तत्काल ही बन्दोबस्त अधिकार के पद पर नियुक्त किया है ताकि वे उन कार्यों को कर सकें जो इस पद के लिए उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं।

[संख्या 7/49/ए०आर०जी०/55-V-II]

जानकी नाथ,

बन्दोबस्त आयुक्त (सी) तथा भारत सरकार
के पदेन अव्वर सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 15th January 1971

S.O. 658.—Whereas, Shri Bishambar Nath Kaushik, son of Shri Jangli Ram 118, Than Singh Nagar, New Delhi, who was a contesting candidate for the mid-term election to the Haryana Legislative Assembly from the Rai constituency held in May, 1968, was disqualified by the Commission by its order dated 23rd January,

1969, under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for his failure to lodge an account of his election expenses as required by the said Act and the Rules made thereunder;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Election Commission for the reasons recorded on the representation made by the said candidate Shri Bishambar Nath Kaushik, reduces the period of disqualification imposed on him to the period of disqualification already suffered by him and removes the disqualification for the unexpired period with immediate effect.

[No. HN/LA/36/68(R).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1971

एस० न्रो० 658—प्रति, विशम्बर नाथ कौशिक सुपुत्र श्री जंगलीराम 118 थानसिंह नगर, नई दिल्ली, जो हरयाणा विधान सभा के लिए मई, 1968 में हुए मध्यावधि निर्वाचन में राय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अधीन आयोग द्वारा उसके आदेश तारीख 23 जनवरी, 1969 द्वारा, उक्त अधिनियम तथा तद्विनिष्ठाएँ गए नियमों द्वारा अपेक्षित अने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण निरहित कर दिए गए थे ;

अतः, अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उक्त अभ्यर्थी श्री विशम्बर नाथ कौशिक द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर अभिलिखित कारणों से उन पर आरोपित निरर्हता की कालावधि को घटाकर उतनी ही करता है जितनी वह वास्तव में सहन कर चुके हैं और अवशिष्ट कालावधि के लिए उस निरर्हता को इसी समय से हटाता है ।

[सं० हरि० वि०स०/36/68 (आर०)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th January 1971

S.O. 659.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorises Shri S. K. Kaul, Personal Assistant in the Embassy of India, Amman, to perform the duties of a Consular Agent from 27th June, 1970 to 3rd September, 1970.

[No. T.4330/2/70.]

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1971

एस० न्रो० 659—राजनयिक और कौंसली अधिकारी (शपथ और शुल्क) अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अन्वय में, केन्द्र सरकार, भारत का राजदूतावास, अम्मान में

सहायक श्री एस० के० कोल को 27-6-1970 से 3-9-1970 तक कौंसली अभिकर्ता का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० एफ० टी० 4330/2/70]

S.O. 660.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorises Shri B. D. Sharma, Assistant in the Embassy of India, Amman to perform the duties of a Consular Agent, with immediate effect, until further orders.

[No. T-4330/2/70.]

P. C. BHATTACHARJEE, Under Secy.

एस० ओ० 660.—राजनयिक और कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, भारत का राजदूतावास, अममान में सहायक श्री बी० डी० शर्मा को इसके द्वारा 27वीं मई से, अगला आदेश होने तक, कौंसली अभिकर्ता का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० एफ० टी० 4330/2/70]

पी० सी० भट्टाचार्य, अवर सचिव।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-TAX

New Delhi, the 10th June 1970

S.O. 661.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (i) of Section 122 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby make the following amendment in the Schedule appended to its notification No. 45 (F. No. 261/8/70-ITJ), dated 31st March, 1970, namely:—

Against Nasik Range, Nasik under column 2, the following shall be added:—
16. Collection Circle, Nasik.

This notification shall take effect from 10th June, 1970.

Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of creation of a new circle, namely 'Collection Circle, Nasik' in the Commissioner's Charge.

(This note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 100 (F. No. 261/8/70-ITJ).]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

आयकर

नई दिल्ली, 10 जून 1970

एस० ओ० 661.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उस को ममर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 45

(फा० सं० 261/8/70-आई टी जे) तारीख 31-3-1970 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

स्तम्भ 2 के अन्तर्गत नासिक रेंज, नासिक के सामने निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

16 वसूली सर्किल, नासिक ।

यह अधिसूचना 10 जून, 1970 से प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकारक टिप्पण

यह संशोधन आयुक्त के भार साधन में एक नए सर्किल, अर्थात् वसूली सर्किल, नासिक के सृजन के कारण आवश्यक हो गया है ।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है)

[स० 100 (फा० सं० 261/8/70-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 15th June, 1970

S.O. 65:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in super-session of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the ranges specified in column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof:—

SCHEDULE

Range 1	Income-tax Circles, Wards and Districts 2
A-Range, Amritsar	<p>1. In respect of orders passed by Income-tax Offices upto and including 14-7-1967:</p> <p>(i) Distt. I Amritsar.</p> <p>(ii) Distt. II(i). Amritsar to Distt. II(v). Amritsar.</p> <p>(iii) Distt. III(i), III(ii), III(iii), III(iv), III(v) and III (vi), Amritsar.</p> <p>(iv) Special Survey Circle, Amritsar [in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Distt. I, II, III(i), III(ii), III(iii), III(iv), III(v) and III (vi). Amritsar.]</p> <p>(v) Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who, reside in the jurisdiction of Distt. I, II and III, Amritsar.)</p> <p>2. In respect of orders passed by the Income-tax Officer, after 14-7-1967:</p> <p>(i) All Circles and wards in Distt. I at Amritsar.</p>
B-Range, Amritsar,	<p>1. In respect of the orders passed by the Income-tax Officers upto and including 14-7-1967:</p> <p>(i) Central Circles I, II and III, Amritsar.</p> <p>(ii) Central Circles I and II, Ludhiana.</p> <p>(iii) Central Circle, Ambala.</p> <p>(iv) Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Central Circles I, II, III, Amritsar and Central Circles, Ludhiana).</p> <p>(v) Special Survey Circle, Patiala (in respect of persons, who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Central Circle, Ambala).</p> <p>(vi) Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who reside in the jurisdiction of Central Circles, I, II, III, Amritsar).</p>

I

2

2. In respect of orders passed by the Income-tax Officers after 14-7-1967:
 - (i) Central Circles, Amritsar.
 - (ii) Central Circles, Ludhiana.
 - (iii) Central Circle, Ambala.
- C-Range, Amritsar 1. All Income-tax Circles. Wards or Districts having headquarters at Amritsar other than those mentioned in column 2 above against A-Range, Amritsar and B-Range, Amritsar.
- Jullundur 1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—
 - (i) Jullundur.
 - (ii) Hoshiarpur.
 2. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Jullundur and Hoshiarpur).
3. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Jullundur and Hoshiarpur).
- Jammu 1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—
 - (i) Jammu.
 - (ii) Srinagar.
 - (iii) Pathankot.
 - (iv) The Income Tax Officer, Charba & Kangra Districts at Pathankot.
 2. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Pathankot).
3. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Pathankot).
- Ludhiana 1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—
 - (i) Ludhiana.
 - (ii) Gurdaspur.
 - (iii) Batala.
 - (iv) Moga.
 - (v) Ferozepur.
 - (vi) Abohar.
 2. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Ludhiana, Gurdaspur, Batala, Moga, Ferozepur and Abohar).
3. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Ludhiana, Gurdaspur, Batala, Moga, Ferozepur and Abohar).
- Patiala 1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—
 - (i) Chandigarh.
 - (i) Patiala.
 - (ii) Sangrur.
 - (iv) Malerkotla.
 - (v) Barnala.
 - (vi) Bhatinda.
 - (vii) Khanna.
 2. Special Survey Circle, Patiala (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of the Income-tax Officers Chandigarh Patiala, Sangrur, Malerkotla, Barnala at Bhatinda).

3. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officer, Khanna).
4. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Chandigarh, Patiala Sangrur, Malerkotla, Barnala, Bhatinda and Khanna).

Where an Income-tax Circle, Ward and District or part thereof stands transferred by this Notification from one range to another range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

Where all Circles, Wards and Districts having headquarters at a particular place have been assigned to an Appellate Assistant Commissioner he will have jurisdiction in respect of Circles, Wards and Districts at that Headquarters since abolished also.

This notification shall take effect from 15-6-1970.

Explanatory Note

The revision of jurisdiction has become necessary on account of re-organisation of the appellate Ranges in the Commissioner's charge.

(The above note does not form a part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 101 (F. No. 261/I/70-ITJ)]
Y. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1970

एस० ओ० 662.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बाबत सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिकाृत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उन सभी व्यक्तियों के और उस आय के संबंध में अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो उस अनुसूची के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, बाडों और जिलों में आयकर या अधिकर के लिए निर्धारित हुई है।

अनुसूची

रेंज 1	आयकर सफिल, बाडों और जिले 2
क-रेंज, अमृतसर	1. 14-7-1967 तक और को सम्मिलित करते हुए आयकर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश की बाबत। (i) जिला I, अमृतसर (ii) जिला II(i), अमृतसर से जिला II(v), अमृतसर। (iii) जिला III(i), III(ii), III(iii), III(iv), III(v) और III(vi), अमृतसर।

(iv) विशेष सर्वेक्षण सिकिल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका, जिला I, II, III (i), III (ii), III (iii), III (iv), III (v) और III (vi) अमृतसर की अधिकारिता में कारबार का मुख्यस्थान है या जो निवास करते हैं)।

(v) वेतन सिकिल, जलन्धर, (उन व्यक्तियों की बाबत जो जिला I, II और III, अमृतसर की अधिकारिता में निवास करते हैं)।

2 14.7.1967 के पश्चात् आयकर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की बाबत :

(i) अमृतसर में जिला I में सभी सिकिलों और वार्ड।

—रंज अमृतसर

1 14.7.1967 तक और को सम्मिलित करते हुए आयकर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश की बाबत :

(i) केन्द्रीय सिकिल I, II और III, अमृतसर।

(ii) केन्द्रीय सिकिल I और II लुधियाना।

(iii) केन्द्रीय सिकिल, अम्बाला।

(iv) विशेष सर्वेक्षण सिकिल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका केन्द्रीय सिकिलों I, II, III, अमृतसर और केन्द्रीय सिकिलों, लुधियाना की अधिकारिता में कारबार का मुख्यस्थान है या जो निवास करते हैं)।

(v) विशेष सर्वेक्षण सिकिल, पटियाला (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका केन्द्रीय सिकिल, अम्बाला की अधिकारिता में कारबार का मुख्यस्थान है या जो निवास करते हैं)।

(vi) वेतन सिकिल, जलन्धर (उन व्यक्तियों की बाबत जो केन्द्रीय सिकिल I, II, III अमृतसर की अधिकारिता में निवास करते हैं)।

2. 14.7.1967 के पश्चात् आयकर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की बाबत :

(i) केन्द्रीय सिकिल, अमृतसर।

(ii) केन्द्रीय सिकिल, लुधियाना

(iii) केन्द्रीय सिकिल, अम्बाला।

ग—रंज अमृतसर

1. सभी आयकर सिकिलों, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालय अमृतसर में हैं क—रंज अमृतसर और ख—रंज अमृतसर के सामने ऊपर स्तंभ 2 में वर्णित को छोड़कर।

1

2

जलंधर

- 1 सभी आयकर सर्किलें, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालयः—
 - (i) जलंधर
 - (ii) होशियारपुर में हैं ।
- 2 विशेष सर्वेक्षण सर्किल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका, आयकर अधिकारी, जलंधर और होशियारपुर की अधिकारिता में कारबार का मुख्यस्थान है या जो निवास करते हैं)
- 3 वेतन सर्किल, जलंधर (उन व्यक्तियों की बाबत जो आयकर अधिकारी जलंधर और होशियारपुर की अधिकारिता में निवास करते हैं)

जम्मू

- 1 सभी आयकर सर्किलें, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालयः—
 - (i) जम्मू,
 - (ii) श्रीनगर,
 - (iii) पठानकोट,
 - (iv) आयकर अधिकारी, पठानकोट में छम्ब और कांगड़ा जिलों में हैं ।
- 2 विशेष सर्वेक्षण सर्किल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका, आयकर अधिकारी, पठानकोट की अधिकारिता में कारबार का मुख्यस्थान है या जो निवास करते हैं) ।
- 3 वेतन सर्किल, जलंधर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका, आयकर, अधिकारी पठानकोट की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है या जो निवास करते हैं) ।

लुधियाना

- 1 सभी आयकर सर्किलें, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालयः—
 - (i) लुधियाना ,
 - (ii) गुरुदासपुर,
 - (iii) बटाला,
 - (iv) मोगा,
 - (v) फिरोजपुर,
 - (vi) अबोहर में है ।
- 2 सब विशेष सर्वेक्षण सर्किल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका, आयकर अधिकारी, लुधियाना, गुरुदासपुर, बटाला, मोगा, फिरोजपुर और अबोहर की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है या जो निवास करते हैं)
- 3 वेतन सर्किल, जलंधर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका, आयकर अधिकारी, लुधियाना, गुरुदासपुर, बटाला, मोगा, फिरोजपुर और अबोहर की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है या जो निवास करते हैं)

पटियाला

- 1 सभी आयकर सर्किलें, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालयः—
 - (i) चंडीगढ़,
 - (ii) पटियाला,
 - (iii) संगरूर,
 - (iv) मलेरकोटला,
 - (v) बरनाला,
 - (vi) भटिंडा,
 - (vii) खप्पा में हैं।
- 2 विशेष सर्वेक्षण सर्किल पटियाला (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका आयकर अधिकारी, चंडीगढ़, पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, भटिंडा में बरनाला की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है या जो निवास करते हैं)
- 3 विशेष सर्वेक्षण सर्किल, भ्रमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका, आयकर अधिकारी, खप्पा की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है या जो निवास करते हैं)
- 4 वेतन सर्किल, जलंधर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका आयकर अधिकारी चंडीगढ़, पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, भटिंडा और खप्पा की अधिकारिता में कारबार का मुख्यस्थान है या जो निवास करते हैं)।

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल, वार्ड और जिला या उसका कोई भाग एक रज से दूसरे रेंज में अन्तर्गत हो गया हो वहां उस आयकर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएंगी और उनके संबंध में कार्यवाही उस सहायक आयुक्त (अपील) द्वारा की जाएगी।

जहां सभी सर्किल, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालय किसी विशेष स्थान पर हैं किसी सहायक आयुक्त (अपील) को समनुदेशित कर दिए गए हैं वहां वह उस मुख्यालय पर स्थित सर्किलों, वार्डों और जिलों पर भी जो अब उत्सादित हो गए हैं, अधिकारिता रखेगा।

यह अधिसूचना 15-6-1970 से प्रभावी होगी

स्पष्टीकारक टिप्पण :

अधिकारिता का पुनरीक्षण, आयुक्तों के भार साधन में अपीली रेंजों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक हो गया है।

(उपरोक्त टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है)

[सं० 101 (फा० सं० 261/1/70-आई० टी० जे०)]

वाई० सिंह, प्रवर सचिव।

